those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned.'

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-five minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

Discussion on the working of the Ministryof Information and Broadcasting

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति जी, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई शक नहीं कि श्री जयपाल रेड्डी जी और इसके बाद श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जबर्दस्त प्रगति हुई है। मान्यवर, कल ही फिक्की और प्राइस वाटर कूपर हाउस की एक स्टडी रिपोर्ट आई है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि एंटरटेनमेंट सैक्टर में 19 परसेंट की ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है। 35 हजार करोड़ से बढ़कर यह सैक्टर एंटरटेनमेंट इण्डस्ट्री 83 हजार करोड़ की होने जा रही है और खाली टेलीविजन विदिन 10 ईयर्स 43 हजार करोड़ का होने जा रहा है। मैं यह बात इसलिए और दावे के साथ कह सकता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज के मामले में इस इण्डस्ट्री का सबसे बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार जिस कदर आप कमा सकते हैं एंटरटेनमेंट इण्डस्ट्री के जरिए, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय फिल्में आज पूरे विश्व में पॉपुलर हो रही हैं। भारतीय स्टार के लिए लंदन से लगाकर मलेशिया,

दुबई और इजप्ट तक तथा यहां सड़कों पर चलना मुश्किल है, चाहे लोग लेंग्वेज न जानते हों लेकिन जिस तरह उनके पीछे-पीछे लोग दौड़ते हैं, जिस तरह से उनको पहचानते हैं, जिस तरह से भारतीय फिल्में देखी जा रही हैं, इस एंटरटेनमेंट इण्डस्ट्री के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि भारत की एंटरटेन्मेंट इण्डस्ट्री ग्लोबली, ओवरसीज इतनी बढ़ने जा रही है। इस समय मौका है कि हमें इसकी तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नॉलेज इकोनॉमी की हम बात करते हैं। नॉलेज इकोनॉमी के दो पहलू हैं। एक आईटी सेक्टर, जिसमें ग्रोथ है और जिसको सारा प्रोत्साहन मिल रहा है और दूसरा एंटरटेनमेंट सेक्टर, जिस पर अभी वह निगाह नहीं आ पा रही है जो निगाह होनी चाहिए। अभी भी हम उसको नाच-गाना की इंडस्ट्री समझते हैं। मुझे लगता है कि यह जो हमारा mindset है, इसे हमें बदलना पड़ेगा। 900 फिल्में कम से कम इंडिया में हर साल बनायी जाती हैं, जो हॉलीवुड से भी ज्यादा हैं। हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स का हाल यह है कि वर्ल्ड का ऐसा कोई देश नहीं है, जहां इंडियन टीवी प्रोग्राम्स, वहां के लोकल चैनल्स, केबल चैनल्स न ले रहे हों - चाहे पूरा अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो - हर जगह इंडियन प्रोग्राम बिक रहे हैं और यहां तक हो रहा है कि वहां पर लोग रीसाइकल करके प्रोग्राम दे रहे हैं। यह अच्छी बात है कि दूरदर्शन के प्रोग्राम भी वहां पर बिकने शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है कि पूरे अमेरिका और यूरोप, सब जगह की डील्स हो चुकी हैं, बाहर विदेशियों को प्रोग्राम देने के लिए, जो ओवरसीज इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं। सर, फिर यह महदूद नहीं है कि केवल इंडियन्स, पाकिस्तानी, नेपाली लोग ही देखते हों या अफगानिस्तानी देखते हों, पूरे सीआईएस कंट्रीज़ के लोग देखते हैं। 80 थिएटर्स में अमेरिका में "लगान" लगी थी। 65 थिएटर्स में "कभी खुशी कभी गम" लगी हुई थी और टीवी प्रोग्राम्स हर जगह पर लोगों ने चलाए हुए हैं। इस प्रकार यह जो इंडस्ट्री है, इसकी जब इतनी अधिक ग्रोथ है, तब हमें निश्चित रूप से इस पर एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए। इसके कैसे प्रोस्पेक्ट्स और ब्राइटन किए जा सकते हैं, कैसे इसे हम और प्रोत्साहन दे सकते हैं, मुझे लगता है कि इस तरफ फोकस करने की जरूरत है। सरकार निश्चित रूप से इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। उसी का नतीजा है कि 19 परसेंट की ग्रोथ प्रोजेक्ट की गयी है। लेकिन इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जब मंत्री जी उत्तर देंगे, तब मैं मंत्री जी से निश्चित रूप से इस बारे में जानना चाहूंगा। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं। मुझे लगता है कि हमारे वित्त मंत्री जी की निगाह थोड़ी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर नहीं है। आईएंडबी मिनिस्टरी तो इसको खूब पुश कर रही है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टरी से इसको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जैसा मिलना चाहिए। सर्विस टैक्स की सारी मार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर है, चाहे वह टेलीविज़न हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो। एक लेखक, टीवी का जो पत्रकार है या एक कवि के ऊपर तो हम सर्विस टैक्स लगाते हैं, लेकिन बड़े-बड़े डॉक्टर्स, बड़े-बड़े वकीलों पर सर्विस टैक्स है ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि अरुण जेटली पर टैक्स लगाओ, रवि शंकर प्रसाद पर लगाओ, आर.के.आनन्द पर भी लगाओ। इन लोगों की आमदनी लाखों और करोड़ों में है। ..(व्यवधान).. सर्विस टैक्स जो है, उसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलो पर तो कम से कम लगाओ। छोटे-छोटे जो लेखक हैं, जिनकी आमदनी पांच-दस हजार है।...(व्यवधान)... चिदम्बरम जी पर भी लगाओ। जिनकी आमदनी पांच-दस हजार है, उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है। राइटर पर सर्विस टैक्स है, जो फिल्मों में गीत लिखते हैं, उनके ऊपर सर्विस टैक्स है, टेलीविजन की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उन सबके ऊपर सर्विस टैक्स लगा हुआ है, वह भी दस से बारह परसेंट कर दिया है। कम से कम दो परसेंट वापस करके उसे दस परसेंट किया जाना चाहिए। इसी तरह जो बड़े-बड़े वकील हैं, जिनकी करोड़ों की आमदनी है -

डाक्टर्स की करोड़ों की आमदनी है, उन पर कोई सर्विस टैक्स नहीं है - यह अन्याय हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। इस तरह से इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस इंडस्ट्री ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : रवि शंकर प्रसाद जी एक्सप्लेन करेंगे, जब वे इस पर बात करेंगे।

श्री राजीव शुक्ल : मैं तो मांग कर रहा हूं कि इन पर लगाइए...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : वह तो शुक्ल जी के घर में ही...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल : कुछ नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी वाले हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): उपसभापति महोदय, पारिवारिक मामलों को कृपया सदन में नहीं लाना चाहिए।

श्री राजीव शुक्ल : मैं तो इसीलिए इनसे टैक्स मांग रहा हूं।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : He is telling about lawyers in general.

श्री उपसभापति : वे और कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आया।

श्री राजीव शुक्ल : अगर इंडस्ट्री पर सारे टैक्स को जोड़ दिया जाए...**(व्यवधान)**... तो तकरीबन 50 परसेंट के करीब जाकर बैठता है। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी तरफ गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Tax should be on the Cricket Board also. ...*(Interruptions)*... And, on the Board of Directors also.

श्री राजीव शुक्ल : वह तो है। क्रिकेट बोर्ड पर 35 परसेंट टैक्स है। प्लेयर्स दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**... किसी को माफ नहीं है। पूरी बीसीसीआई पर टैक्स है, क्रिकेटर्स पर टैक्स है, ऑफिस बीयरर्स पर टैक्स है, किसी को कोई छूट नहीं है। टोटल एक्ज़म्शन ही खत्म कर दी है। वे तो दे ही रहे हैं, लेकिन मैं तो इनकी बात कर रहा हूं। मान्यवर, मैं दूसरी बात दूरदर्शन पर, क्वालिटी प्रोग्राम्स के बारे में कहना चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दस सालों में दूरदर्शन के प्रोग्राम्स में पूरी तरह से गिरावट आई है। जिसके कारण ऑल्मोस्ट लोगों ने दूरदर्शन के प्रोग्राम्स देखने बंद कर दिए। खास तौर से शहरों में, अबर्न एरियाज में, जहां पर Satellite TV उपलब्ध है, लोगों ने वहां दूरदर्शन प्रोग्राम देखने बंद कर दिए, क्योंकि दूरदर्शन में क्वालिटी प्रोग्राम्स बिल्कुल नहीं थे। उनमें धीरे-धीरे कमी होती चली गई। एक जमाना था जब महाभारत तथा एक से एक बढ़कर प्रोग्राम्स आते थे, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे यह गिरावट आई, जब से स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम का सिस्टम लागू किया गया। मान्यवर, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, उसमें यह होता है कि दूरदर्शन स्लॉट दे देता है और वह प्रोड्यूसर से उसके पैसे लेता है। उसके बाद प्रोड्यूसर उसी को बाजार में जाकर बेचता है, जो उसको FCT अर्थात, फ्री कमर्शियल टैक्स मिलता है। उससे जो पैसा आता है, उससे वह प्रोग्राम या जो भी उसे करना होता है, वह करता है। FCT बिकता नहीं है, क्योंकि जब बाजार में इतनी FCT फ्लोट हो गया है, अगर आप उसके दो हजार प्वाइंट FCT देते हैं तो दूसरा कह रहा है कि हम एक ही हजार

देने को तैयार हैं और तीसरा कह रहा है, हम सात सौ में देने को तैयार हैं। नतीजन, यह होता है कि धीरे-धीरे प्रोग्राम्स में लोग कम्प्रोमाइज करते गए और उसकी क्वालिटी से कम्प्रोमाइज करते गए। जो भी दूरदर्शन का CO या DG होता था, उसकी सक्सेस का यह सिम्बल बना दिया गया, यह yardstick बना दी गई कि यह कितने पैसे कमाकर देता है? उसे एक तरफ से दुकानदार बना दिया गया। उसकी सक्सेस पैसों में नाप दी गई, उसका जो social obligation था, जो नेशन के प्रति ऑब्लिगेशन था, आम जनता के प्रति जो ऑब्लिगेशन था, उसको छोड़कर यह हो गया कि इस DG ने इतने 100 करोड़ कमाकर दिए, इसने इतने कम कमाकर दिए। इसलिए जब यह बन गया तो DG और CO के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वे हर बार यह करते कि वे प्रोड्यूसर के लिए टैलीकास्ट की फीस बढ़ा देते थे। इससे यह नतीजा हुआ कि दूरदर्शन के प्रोग्राम्स में गिरावट आती गई। आपको एक जमाना याद होगा, जब DD मैट्रो खुला था और उसपर कमिशनिंग प्रोग्रामिंग थी। मैं आपको बताता हूं कि उस पर न केवल प्रोग्राम लेने के लिए भीड़ लगती थी, बल्कि इतने अच्छे प्रोग्राम उस पर आते थे कि हर आदमी उसी को देखना चाहता था। मैं प्रियरंजन दास मुंशी जी को बधाई देना चाहूंगा और जो उनके प्रेडिसेसर, श्री जयपाल रेड्डी जी हैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं CO प्रसार भारती को और DG को भी बधाई देना चाहूंगा कि इन लोगों ने फिर से वह प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया अभी पूरी तरह से शुरू नहीं की है, लेकिन कम से कम इसकी शुरूआत तो की है और कमीशन कैटेगिरी में कुछ प्रोग्राम देने शुरू किए हैं, ताकि Quality programmes आने शुरू हों। मुझे लगता है कि यह स्कीम सक्सेस हो रही है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको और बढ़ाएं तथा और अच्छी प्रोग्रामिंग लाने के लिए कमिशनिंग शुरू करवाएं। उनको CBI से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल होता यह है कि दूरदर्शन में सुबह से शाम तक CBI घूमती रहती है। इसका नतीजा यह होता है कि यदि एक भी डिसिजन लिया तो कम्पलेंट हो जाएगी। इसलिए यहां डिसिजन लेने में सब डरते हैं, यदि एक को प्रोग्राम दे दिया और दूसरे ने कम्पलेंट कर दी तो CBI इंक्वायरी हो जाएगी। इसलिए इसके लिए एक फुलप्रूफ सिस्टम बना दिया जाए। अगर ऐसे ही CBI से डर गए तो कुछ नहीं होगा। बाकायदा और जो कमेटियां हैं वे सब देखकर निर्णय लें और जो क्वालिटी प्रोग्रामिंग है, उसको लें, डरने से कुछ नहीं होगा। इसमें बिल्कुल साहस और हिम्मत से काम लेकर, यह सब करना चाहिए, ताकि उसकी क्वालिटी प्रोग्रामिंग इम्प्रूव हो। इसमें कोई शक नहीं है कि DD News में जो हालत पहले थी, अब उसमें सुधार हुआ है । मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वे इसमें और professionals को लाने की प्रक्रिया शुरू करें। वहां पर professionals आए भी हैं, कुछ और professionals भी वहां पर लाए जाएं। दूसरा, यह है कि DD News का बजट इक्वेपमेंट के लिहाज से और दूसरे तमाम लिहाज से budget allocation भी बढ़ाया जाए। ठीक है, आपने उसको स्टूडियो और सब कुछ अच्छा दिया हुआ है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसी चीजों की कमी है, इस तरह के स्टाफ और इक्विपमेंट की कमी है, जो Satellite TV चैनल्स हैं, प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं, उनका मुकाबला करने में, उसको दिक्कत आती है। उसे दूर करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से TRP सिर्फ पांच आती है। पांच TRP होने से रेवेन्यु जनरेशन पर भी बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टर है, जो उसका न्यूज चैनल है, वह BBC के पैटर्न पर, कम से कम उसकी reach और क्रेडिबिलिटी हो कि पूरा देश उस पर इस निगाह से देखे कि यहां आपको सही खबर मिलेगी, इन्टरेस्टिंग खबर मिलेगी। मेरे लिहाज से, इसीलिए इसका बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें और professionals लाने की आवश्यकता है। अगर आपको

लगता है कि बाहर से प्रोग्राम्स outsource करने में फायदा है तो इससे उस चैनल की और डिमांड बढ़ेगी, इसलिए यह भी करना चाहिए। DD News को और अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, FM रेडियो का रेवोल्युशन भी आ गया है। पिछले चार साल से उसको लेकर एक गलती हो गई थी। जिसमें उसकी लाइसेंस फीस इतनी ज्यादा हो गई थी कि FM Radio का concept, जिसके बारे में यह विचार था कि यह revolution होगा, वह successful नहीं हो पाया, क्योंकि जो लोग रेडियो चलाते थे, वे उसकी लाइसेंस फीस नहीं दे पाते थे और सबसे बड़ी दिक्कत यह आती थी कि उनको इतना घाटा होता था कि वे FM Radio का संचालन नहीं कर पाते थे, केवल इक्का-दुक्का लोग रहे होंगे, जो इसको अच्छी तरह से कर पाते थे। फिर FICCI ने काफी स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया था कि कुछ लाइसेंस फीस और कुछ revenue sharing basis पर FM Radio दिए जाएं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने इस योजना को लागू किया और इस योजना को लागू करने का नतीजा यह हुआ कि आज FM Radio का revolution एक तरह से शुरू होने जा रहा है, पूरे देश में FM Radio के स्टेशनों का auction हो चुका है, उनकी bids कर दी गई हैं। सरकार को अभी केवल लाइसेंस फीस में करीब एक हजार करोड़ रुपया मिला है, जो एक अच्छी शुरुआत है, आगे revenue sharing basis पर यह और बढ़ेगा। इसलिए FM Radio का जो यह revolution आया, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। अगर इसमें revenue generation ज्यादा होगा, सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी, तो इससे सरकार का भी revenue बढ़ेगा और यदि FM Radio पूरे देश में successful हुआ, तो यह entertainment का न केवल बहुत बड़ा जरिया होगा, बल्कि आगे retail business और छोटे-छोटे जो इस तरह के business हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा basis बनने जा रहा है। इसकी पूरी publicity और popularity, FM Radio पर निर्भर करेगी। इसलिए इस ओर सरकार ने जो ध्यान दिया है, मुझे लगता है कि उसकी जितनी सराहना की जाए, वह कम है।

उपसभापति जी, मैं निश्चित रूप से TRP के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि DD News की TRP 5 ही है। यह सिर्फ केबल और satellite homes को count करके दे देते हैं। जो terrestrial के जरिए, पूरे देश में उसकी अपनी reach है, लगता है कि उसकी कहीं कोई गणना नहीं होती है, क्योंकि TRP का mechanism हमने प्राइवेट हाथों में दे रखा है। एक प्राइवेट कंपनी है, मेरे ख्याल से उन्होंने मुश्किल से 4-5 हजार मीटर लगाए होंगे या बहुत ज्यादा होगे तो 10 हजार मीटर लगाए होंगे। एक अरब की आबादी में 4 हजार या 5 हजार मीटर लगाकर आप कैसे जज कर सकते हैं कि कौन से लोग क्या प्रोग्राम देखना चाहते हैं? एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से यह जो गणना होती है, उसका असर हजारों करोड़ रुपए की उस किटी पर पड़ता है, जो different channels को जाती है, जो different television programmes को जाती है और उसकी वजह से जो सही स्थिति है, वह लोगों के सामने नहीं आ पाती है और धीरे-धीरे यह हो गया है, मुझे कहते हुए दुःख होता है कि आज केबल माफिया बन गए हैं। हर चैनल का एक hidden budget होता है और वह hidden budget करोड़ों रुपए का होता है, जो कुछ cable operators को दिया जाता है, जो आपके चैनल को सही बैंड पर रखने की कोशिश करते हैं। आपके टी.वी. पर शुरुआत के 1 से 10 नंबर पर जिस चैनल को डालना है, इसके लिए वह पैसा दिया जाता है। अगर किसी चैनल का पैसा नहीं पहुंचा, चंदा नहीं पहुंचा, तो उस चैनल को 50 और 60 नंबर पर डाल दिया जाता है, ताकि लोग उसको न देखें। इससे उसकी TRP नीचे चली जाएगी और यदि TRP नीचे चली जाएगी,

तो उसका जो advertisement collection है, वह नीचे चला जाएगा, उसका revenue collection नीचे चला जाएगा। इसलिए मेरी अपनी मांग है कि TRP के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एक कमीशन बनाना चाहिए, चाहे उसमें आप judicial commission की तर्ज पर रिटायर्ड जज रखिए, उसका पूरा एक professional mechanism होना चाहिए और TRP की जानकारी लेने के लिए कम से कम एक लाख मीटर होने चाहिए। आपको पता है कि बिहार में मीटर ही नहीं लगाया है, क्योंकि जो एजेंसी इस काम को करती है, उन लोगों की thinking यह है कि बिहार के लोगों के पास purchasing power नहीं है, इसलिए वहां TRP मीटर की जरूरत नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के पास purchasing power है, इसलिए वहां TRP मीटर लगाने चाहिए। अरे, क्या बिहार के लोग कपड़े नहीं पहनते या तेल नहीं खरीदते या साबुन नहीं खरीदते या साईकिल नहीं लेते या मोटर-साईकिल नहीं लेते या टी.वी. नहीं लेते? बिहार के लोग हर चीज खरीदते हैं, East UP के लोग भी खरीदते हैं, उड़ीसा के लोग भी खरीदते हैं, लेकिन यह जो TRP मीटर हैं, इनके बारे में इन लोगों ने मान लिया है कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, मुंबई बहुत अच्छा है, गुजरात बहुत अच्छा है, कानुपर अच्छा है, इस तरह उन्होंने कुछ शहर चुन लिए हैं और उन शहरों में मीटर लगाकर, वे उसी basis पर determine करते हैं कि किस प्रोग्राम की क्या popularity है किस चैनल की क्या popularity है, इसलिए इसमें manipulations होने शुरू हो गए और इसीलिए ये पैसे दिए जाने लगे। मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, राजस्थान के एक शहर में एक liquor baron के पास cable operation का काम है, उसके area में एक TRP मीटर लगा हुआ है, जिस चैनल के पैसे उसके यहां पहुंचते हैं, उसको तो वह TRP मीटर पर लगा देता है। तो वह चैनल पॉपुलर हो जाता है। जिसका पैसा जिस महीने नहीं पहुँचता है, उसको उससे हटा देते हैं। उसकी टीआरपी 36 परसेंट डाऊन हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि उसका मार्केट शेयर गिर जाता है। इससे उसका रेवेन्यू भी उतना ही कम हो जाता है। यह टीआरपी वाली एक बड़ी गम्भीर समस्या है। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देकर कोई ऐसा काम करना चाहिए, जिससे कोई एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस आर्गेनाइजेशन हो, जो इस पर ध्यान दे। जब यह टेलीविजन इंडस्ट्री 42 हजार करोड़ की हो जाएगी, तो उसके लिए किसी प्राइवेट एजेंसी के हाथ में टीआरपी का सिस्टम रखना, मैं नहीं समझता कि उचित है। इसलिए इसके लिए कम-से-कम लॉक मीटर होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस आर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो इसको देखे और इस पर काम करे।

सर, अभी डीटीएच भी आया हुआ है। दूरदर्शन का डीटीएच सक्सेसफुल हो रहा है। इसके लिए मैं सरकार को और मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। इसकी और रीच बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन क्या मंत्री जी इसे थोड़ा क्लियर करेंगे कि प्राइवेट लोगों को जो डीटीएच दिए जा रहे हैं, वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं? क्या इसमें कोई डिसक्रिमिनेशन हो रहा है? क्योंकि इस तरह की शिकायतें भी आती हैं कि किसी की अप्लिकेशन थ्रू और किसी की अप्लिकेशन थ्रू नहीं होती है। किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर प्राइवेट डीटीएच दिया जा रहा है? प्राइवेट डीटीएच देने के लिए क्या पॉलिसी है, यह अगर मंत्री जी स्पष्ट करें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा।

एक नया जजमेंट आ गया है - कैस का। कैस का नाम सुनते ही रवि शंकर प्रसाद जी एकदम खड़े हो जाते हैं, अरुण जेटली जी की नींद खुल जाती है, क्योंकि यह इन्हीं की देन

जिसका आज तक स्यापा नहीं सिमट पा रहा। सुषमा जी ने शुरू किया और रवि शंकर प्रसाद जी तक गया, उसके बाद इतना तमाशा हुआ कि खुराना जी कूद गए और खुराना जी ने इसे कैंसल कराया। अब फिर हाई कोर्ट का जजमेंट आया। इनकी मुसीबत फिर हमारे सर पर आ गई है। मैंने कहा कि मुंशी जी तो मुंशी जी हैं, वे इसका कुछ-न-कुछ रास्ता निकालेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन जो भी जनहित में हो, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो हमें लगता है कि वैसा करना चाहिए। इसके लिए आपको कितने भी सख्त कदम उठाने पड़ें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है।

सर, मैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ी-सी कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा भी थोड़ा-बहुत राफ्ता रहता है और हमारी जान-पहचान लोगों से है। इससे हमें तमाम समस्याओं का आइडिया लगता रहता है। हिन्दुस्तान 900 से ज्यादा फिल्में बनाता है। श्याम बेनेगल साहब भी यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये भी इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। 900 से भी ज्यादा फिल्में भारत बनाता है। अभी तक इस इंडस्ट्री की हालत यह रही है कि इसमें जबर्दस्त फाइनेंसियल क्राइसिस रही है, धनाभाव रहा है। पैसे की कमी से न केवल कलाकारों का, बल्कि डायरेक्टर्स का और पूरी इंडस्ट्री का शोषण होता रहा है। मुझे इस मामले में सुषमा जी की प्रशंसा करने में कोई हर्ज़ नहीं है कि उन्होंने इसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि फिल्मों को बनाने के लिए लोन मिलना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी आईडीबीआई जैसी संस्थाएँ लोन देती हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा पड़ता है कि वे फिल्में कहीं भी फाइनेंसियली वायबल नहीं हो पाती हैं। उनकी दिक्कत वैसी ही बरकरार है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में क्रेडिबल प्रोड्यूसर्स को, भले कोलैटरल वगैरह लें, उसकी बेसिस पर अगर फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देने का प्रोसेस शुरू किया जाए, तो इससे उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी।

सर, अब वक्त आ गया है, जब हमें एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी बीपीओ की बात सोचनी चाहिए। हॉलीवुड के तमाम लोग अपने फिल्मों की एडिटिंग, अपने फिल्मों का बहुत-सा काम इंडिया को देना चाहते हैं, बशर्ते कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के नाम पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। बॉम्बे में, गोरेगाँव में हमारी एक फिल्म सिटी है, हमारे पास वही एक है, लेकिन वह भी 30 साल पुराना हो चुका है। इसमें न तो आधुनिक स्टुडियो है, न कोई इक्विपमेंट है, न उस तरह की लोकेशंस हैं, सारी घिसी-पिटी लोकेशंस हो चुकी हैं। इसलिए एक तो बॉम्बे फिल्म सिटी को एक नया रूप दिया जाए, इसके अलावा जो प्राइवेट लोग नई फिल्म स्टुडियो, हाईटेक स्टुडिओ, कंवर्जेंस स्टुडियो लगाने के लिए आगे बढ़ कर आएँ, तो मुझे लगता है कि उनको सरकार की तरफ से इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि अगर हमारे पास फिल्म मेकिंग का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हजारों करोड़ की आएगी। बाहर के लोग यहाँ पर फिल्में बनवाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, टेक्निशियंस बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, तो बीपीओ का बाहर का बहुत सा काम आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसी चीज है कि हमें उस का पूरा फायदा मिल सकता है। अभी दुबई ने अपने यहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को शूटिंग करने को एनकरेज करने के लिए बहुत कुछ किया है। मलेशिया भी कर रहा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर

महातिर जी अभी तक खुद इंटरेस्ट लेते थे और इंडियन फिल्म स्टार शाहरुख खान वगैरह को फोन कर कहते थे कि हमारे यहां शूटिंग करो, हम आप को यह फेसिलिटी देंगे। दुबई ने इंडियन फिल्म स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बैसेडर बनाया है। वहां के लोग ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, आमिर खान और सब को बुलाकर बोलते हैं। इसलिए हमें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर उन को बाहर के लोग ब्रांड एम्बैसेडर बनाकर अपने यहां शूटिंग करने के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड वाले लगातार सुविधाएं देते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमें भी अपने यहां यह इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करना चाहिए। हम उन को एनकरेज करें, उन को मदद दें और उन को सिर्फ नाच-गाने की इंडस्ट्री न मानें। हमें उन को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री के सारे बेनेफिट्स हमें मिले। इस से जो फॉरेन एक्सचेंज जनरेशन होगा, उस से हमारे यहां एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सर, एक टी.वी. सीरियल से 700 लोगों को नौकरी मिलती है। अब सोचिए हमारे यहां हजारों की तादाद में सीरियल्स बन रहे हैं, एक हजार फिल्में हर साल बनती हैं तो इस से कितने लाख लोगों को नौकरियां व जॉब मिल सकता है। यह इंडस्ट्री इतनी जॉब ओरिएंटेड और जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्री है जिस का बहुत बड़ा फायदा हमें मिल सकता है। सर, यहां दो महारथी बैठे हैं जोकि आई. एंड बी. मिनिस्टर रहे हैं। अरुण जेटली जी भी रहे हैं। इन के जमाने में भी इस दिशा में काफी काम हुआ है और मान्यवर भी बैठे हैं। ...**(व्यवधान)**... अब मैं क्या बोलूं, मेरा विरोध करने के लिए अभी खड़े हो जाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि सब को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।

महोदय, एक सब से बड़ी समस्या "पायरेसी" की है। मान्यवर, यह एक बड़ी समस्या है जिस की वजह से इंडियन फिल्मों को काफी नुकसान होता है। मुझे इस की थोड़ी जानकारी है। सोनीपत के पास कोई क्लैंडेस्टिन बिजनेस ग्रुप है। वहां इंडस्ट्री लगी हुई है और वह थिएटर से उस की कॉपी बनाते हैं। एक रात में कम-से-कम 5 हजार कॉपी बनाकर बाहर भेज देते हैं। ये कॉपीज दुबई जाती हैं और दुबई के रास्ते पाकिस्तान चली जाती हैं, लेकिन जिस का एंडिवर है, जिस का क्रिएशन है, जिस ने फिल्म बनायी है, अपना पैसा लगाया है, एकजुट होकर जिन लोगों ने काम किया है, उन को इस का कोई फायदा नहीं होता है। इस का पैसा भारी तादाद में बिना कुछ किए ले जाते हैं। पाकिस्तान की पूरी म्यूजिक व फिल्म इंडस्ट्री इंडिया पर डिपेंडेंट है। वहां शॉप्स पर आप को इंडियन म्यूजिक व इंडियन फिल्म की सी.डी. मिल जाएंगी। हर घर में लोग इंडियन गाने सुन रहे हैं, लेकिन वहां से एक पैसा भी इंडिया को रिपाट्रिएट होकर नहीं आता है। यहां के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स व एक्टर्स को कुछ नहीं मिलता है, सारा पैसा बीच के बिचौलिए जो माफिया हैं, वे दुबई के माध्यम से ले जाते हैं। हमें इस संबंध में ऑफिसियल लेवल पर मुशर्रफ साहब से बात करनी चाहिए कि हम एक ऑफिसियल एग्रीमेंट करें और आप हमारी फिल्म्स और म्यूजिक वहां रिलीज करवाइए। आप भी टैक्स का पैसा लीजिए और हम भी पैसा लें और जिस का क्रिएशन है, जिस का इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उस को फायदा मिले। ये बीच के लोग जो मुफ्त में सारा फायदा ले जाते हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने एक बार उन से बात की थी, लेकिन वह उस पर एकदम से चुप हो गए। उन्हें लगता है कि उन के यहां इंडिया का कल्चरल इनवेजन हो जाएगा। मैं उन को बताना चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी को छोड़ दें। आप के यहां इंडिया का कल्चरल इनवेजन हो चुका है क्योंकि आप ने अपने यहां एंटरटेनमेंट चैनल्स सब अलाउ किए हुए हैं। वहां स्टार प्लस आता है, सोनी आता है, वहां "जी" आता है

3.00 P.M.

और वहां सहारा आता है। वहां के लोगों को श्लोक तक याद हो गए हैं, वहां के लोगों की हिंदी इम्प्रूव हो गयी है। उन्हें पता है, यहां कैसे शादी होती है और क्या-क्या होता है। वहां के लोग यहां की एक-एक चीज देख रहे हैं और हम से ज्यादा वे लोग जानते हैं। उन की बातों में कई ऐसे वर्ड्स निकलने लगे हैं जो यहां पॉपुलर हैं। वहां इंडियन टी.वी. सीरियल्स इतने पॉपुलर हैं कि लोग अपने घर नहीं छोड़ते जब वहां इंडियन टी.वी. सीरियल्स आते हैं। तो जब इंडियन टी.वीज., सैटेलाइट टी.वीज. वहां पहुंच रहे हैं तो आप किस कल्चरल इनवैजन की बात करते हैं? इसलिए आप वहां इंडियन फिल्म्स को इजाजत दें भले ही उस के लिए अपना स्क्रीनिंग बोर्ड रखें और उस स्क्रीनिंग बोर्ड के जरिए परखें कि उस में कोई चीज एंटी-पाकिस्तान न हो। अगर पाकिस्तान की उस टैरेटरी को खोला जाए और उन से बात चलायी जाए तो मुझे लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लाभ होगा और उन को भी होगा। इस तरह जो लोग पायरेसी करते हैं, गवर्नमेंट को उन के ऊपर जबर्दस्त क्रैक-डाउन करना चाहिए। महोदय, फिल्म फेस्टिवल भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने गोवा में फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की है। रवि शंकर जी यहाँ बैठे हैं, उसमें इनका काफी योगदान था। अब उस केन्द्र को और आगे बढ़ाना है। अगर हम गोवा फिल्म फेस्टिवल को Cannes की तर्ज पर, उस स्तर पर ले जाएँ, तो कोई मुश्किल नहीं होनी है। अगर हम उसकी इंटरनेशनल ब्रांडिंग करें, तो गोवा फिल्म सेटर भी Cannes की तर्ज पर एक बड़ा पॉपुलर सेंटर हो सकता है। आज देश को इसकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के मामले में हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड सबसे ज्यादा मशहूर है और सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है। इसलिए अगर हम गोवा फिल्म फेस्टिवल को और एनकरेज करें,

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

उसकी इंटरनेशनल पब्लिसिटी करें, इंटरनेशनल ब्रांडिंग करें, उसका बजट बढ़ाएँ और उसको स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से लेकर इनफॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही देखना शुरू करे, तो ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि कई बार स्टेट गवर्नमेंट का वह विज़न नहीं रहता है, जो होना चाहिए। इसलिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सीधे अपने हाथ में ले ले और खुद उसका आयोजन करे, साथ ही इसकी जो भी फी या रेवेन्यु जेनरेशन होता है, उसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट को मिले, लेकिन इसका आयोजन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। इससे हम इस गोवा फिल्म फेस्टिवल को Cannes की तर्ज पर बहुत आगे ले जा सकते हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात और कहना चाह रहा था कि फिल्म सेंसर बोर्ड को किस तरह से और स्ट्रेथेन किया जा सकता है। फिल्म सेंसर बोर्ड का हाल भी वैसे ही प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया की तरह होता चला जा रहा है, जिसके कोई नाखून नहीं हैं, जिसके कोई दाँत नहीं हैं। मैं तो समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म सेंसर बोर्ड से ज्यादा डर बाहर के ऐसे लोगों का है, जिनके द्वारा वाइल्ड लाइफ को लेकर काफी हंगामा चलता रहता है। अगर किसी ने अपनी फिल्म में एक हाथी, एक घोड़ा या एक ऊँट भी दिखा दिया, तो लोग पहले उनके यहाँ जाकर मत्था टेकते हैं, हाजिरी दे कर कहते हैं कि भाई आप ऑब्जेक्शन मत करना। लोग उनके यहाँ से क्लीयरेंस लेने के बाद फिल्म रिलीज़ कराते हैं। मंत्री जी फिल्म सेंसर बोर्ड को स्ट्रेथेन करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं और वायलेंस और ऑब्सीन फिल्मों को रोकने

के लिए क्या नजरिया अपना रहे हैं? जैसे मैं अभी एक फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी एक फिल्म देखी, जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन वह यूथ को क्या मैसेज देती है? वह फिल्म यूथ को यह मैसेज देती है कि किसी ने रेडियो पर सुन लिया कि एक डिफेंस डील हुई, जो डील गलत थी। इसकी वजह से एयर फोर्स का एक विमान था, वह क्रैश कर गया, जिसमें उसके दोस्त की मौत हो गई। कॉलेज के उस लड़के ने डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ घुस कर उसको मार डाला, चूँकि विमान की खरीद में गड़बड़ी हुई होगी, तो इसके लिए डिफेंस मिनिस्टर रेस्पॉंसिबल है, इसके कारण ही मेरा दोस्त, जो उसमें पायलट था, वह मरा। इसलिए डिफेंस मिनिस्टर को चल कर मार देना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... यह क्या मैसेज दे रहा है? अगर ये चीजें एक बार ऐसे हाथों में आ गईं, तो फिर सब बनेगे न, डिफेंस मिनिस्टर, बारी-बारी। उसमें वायलेंस दिखाने की भी कोई सीमा होनी चाहिए, फिल्म किसी लॉजिकल एंड पर पहुँचनी चाहिए। इसके पहले भी एक फिल्म थी, जिसका नाम मैं नही लेना चाहूँगा। अगर कायदे से देखें तो "बंटी और बबली" में भी क्या दिखाया गया, यही conmanship कि आप कैसे लोगों को चालाकी से, ट्रिक से या होशियारी से, बेवकूफ बनाएँ और उनसे पैसे ठगे। उसमें यही तो है। यह जो मैसेज है, इस मामले में फिल्म सेंसर बोर्ड को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री अरुण जेटली (गुजरात): आप फिक्शन पर भी एतराज कर रहे हैं?

श्री राजीव शुक्ल : नही, हम फिक्शन पर एतराज नहीं कर रहे हैं। हर फिल्म का कहीं-न-कहीं, कुछ-न-कुछ मैसेज होना चाहिए ...(**व्यवधान**)... उसमें कुछ-न-कुछ मैसेज होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मैसेज की बात तो वृंदा जी, सबसे ज्यादा आप करती हैं। इसलिए फिल्मों का जो सेंसर बोर्ड है, उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि उस फिल्म का मैसेज अल्टिमेटली क्या निकल रहा है। उसका मैसेज लोगों को अच्छा बनाने के लिए जा रहा है या लोगों को बिगाड़ने के लिए। यह एक बहुत जरूरी चीज़ है।

एक और चीज़ यह है कि हमारा ए.बी.सी. के जरिए न्यूज़ पेपर सर्कुलेशन का जो मेथड है, उसको लेकर पेपर्स में बड़ी वार चलती रहती है। कोई कुछ क्लेम करता है और कोई कुछ क्लेम करता है। आज तक कोई एक सही और साफ तस्वीर नहीं आ पाती कि किसका सर्कुलेशन ज्यादा है, किसका सर्कुलेशन जेन्युन है, किसका सर्कुलेशन लेजिटिमेट है। किसने रिकॉर्ड्स की fudging की है और किसने क्या किया, इसको लेकर बहुत ही दिक्कत रहती है। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि इस मामले में भी कोई ऐसा क्रेडिबल सिस्टम लाएँ और बताएँ कि उनकी क्या योजना है, ताकि न्यूज पेपर सर्कुलेशन के मामले में सही बात सामने आ सके।

मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा और मुझे लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया सामने से हो सकती है। एक "इंडिया शाइनिंग कैम्पेन" हुआ था, जिस पर करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए थे। वह पैसे कहां से आए? क्या वह पैसा आई. एंड बी. मिनिस्टरी से आया था या कहां से लाया गया था? क्या इलेक्शन के पहले इस तरह का कैम्पेन एलाउ करना चाहिए, जिसमें उस सरकार का पूरा महिमा-मंडन हो, उस सरकार की प्रशंसा हो? एक तरह से यह इलेक्शन कैम्पेनिंग इंडिया-शाइनिंग कैम्पेन था। तो क्या चुनाव के पहले इस तरह का कोई इंडिया-शाइनिंग जैसा कैम्पेन एलाउ किया जाना चाहिए? इसके बारे में मंत्री महोदय का नजरिया क्या है? कितने पैसे उस पर खर्च हुए थे और वह पैसा किस मिनिस्टरी से आया था? अगर मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं पूना इंस्टीट्यूट के बारे में कहना चाहता हूँ। यह एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और आई. एंड बी. मिनिस्टरी के तहत आता है, लेकिन यह बहुत नेगलेक्टेड रहता है। आज जगह-जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं और आप देखें कि किस तरह यूथ का जो टेलेण्ट है, वह निकल कर आ रहा है। उनको अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस पूना इंस्टीट्यूट को और अधिक अच्छा बनाया जाए, इसकी और ब्रांचें खोली जाएं, इस का और विस्तार किया जाए, इसका बजट बढ़ाया जाए, तो यह अच्छा होगा।

महोदय, आखिरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली बार, जब सुषमा जी मिनिस्टर थीं, उन्होंने यह बात रखी थी कि एक मीडिया कौंसिल बनानी चाहिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया के लिए तो प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया है, हालांकि बहुत एफेक्टिव नहीं है, फिर भी है लेकिन, आप वहां अपनी शिकायत दे सकते हैं, लेकिन टी.वी., न्यूज चैनल के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसी कौंसिल या कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, जहां आप अपनी बात रख सकें। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि इस पर कोई सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेस कौंसिल की तर्ज पर कुछ अधिकार के साथ जुडिशियरी के लोगों की और पत्रकारों की मिलकर कोई बॉडी हो, तो उस सुझाव पर विचार करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Hon. Vice-Chairman, Sir, I am grateful that you have given me the opportunity to make my comments on the working of the I&B Ministry. Sir, this debate has begun in a very curiously interesting way. The debate was initiated by an hon. Member who has been, or may be he is, a media personality and it is being followed by a Member who had an occasion to handle this Department in different capacity. What is further interesting is that I see Priya*babu* deeply engrossed. I hope he is listening to what I am going to say. I am happy that he has found some time from his pressing Parliamentary commitments as a Parliamentary Affairs Minister to give some time to the equally important I&B Ministry. Therefore, I would begin with a query to the hon. Minister. How do we take the I&B Ministry? Is it a Ministry of Doordarshan or AIR? Or, does it have a larger role? Doordarshan and AIR are important, indeed, very important. I would make my comments subsequently on this. But, what is the larger canvas of this Ministry must not be lost sight of, because quite frequently we hear observations as to what is the relevance and rationale of the I&B Ministry. Because of the power and technology, we are heading towards convergence. Let there be a super communication Ministry. These kinds of observations we do hear. Therefore, Mr. Minister, may be it is the occasion to discuss the working of your Ministry, I would like a very categorical stand from your Government, as to how do you take convergence. Are you going to initiate

convergence? Are you going to carry it forward? Will it also take into account all the working of the telecommunication and all the source of media entertainment which, at some point of time, are converging technologically? This is an important issue. As far as I am concerned, Sir, I am very clear that the I&B Minister has a very crucial role to play. It is a Ministry which takes care of the AIR and Doordarshan, which initiates the whole policy of entertainment -- of films, of media, of television, of music. What not, apart from print and management of press by the PIB? Therefore, this larger role always needs to be considered in mind. When I talk of entertainment, I remember when I had some time to handle this Department, Sir, I had coined an expression that, "If the 90's were the decade of IT and Communication, the first decade of the 21st Century is the decade of Indian entertainment." When I said that, there were certain comments. Recently, Sir, I was going through an observation of a very senior executive of the Walt Disney Company, Mr. Mark Zoradi who had come to India. He stated that Disney had identified India along with Russia and China as the target markets that would power the entertainment major growth over the next decade. The entire world is today coalescing in India, hon. Minister, in the field of entertainment, in the field of television. I am quite sure they may be making a beeline to you as well. Why so? The rate of growth of this sector is 18 per cent. Mr. Shukla gave certain statistics. It has immense potential; the Indian entertainment has enough potential to boost the Indian economy. Therefore, I say it is very important that there must be a change of mindset in the entire functioning of the I&B Ministry as to how we wish to carry forward this sector. Mr. Minister, the first query, therefore, would be: Does the Ministry possess that mindset? Two-fold responsibilities are there on the Ministry: (a) to come with policy initiative which further power this growth, and (b) make Doordarshan and Akashwani, the eminently desirable public broadcasters, educators, entertainers, and social informer, to continue with their job along with professionally becoming competitive. These are the twin obligations of the Ministry of I&B. In this context, we have to consider the functioning.

Sir, let me begin with Prasar Bharati first, because Prasar Bharati is an autonomous body overseeing the functioning of the AIR and Doordarshan, obviously in connection with the Ministry. Mr. Minister, I hope you are aware that you have many vacancies in Prasar Bharati. The Member (Finance) is non-existent for the last more than one-and-a-half years. The Member (Personnel) is not there. Three Members have demitted, and one died, Mr. Vidya Nivas Mishra, a very eminent literary

person of the Hindi literature. Now, you are having probably two full-time Members and two part-time Members. I am quite sure whenever a vacancy is going to occur, the Department is aware of that. There is a process of filling all these vacancies. Why this kind of *ad hoc* approach, I fail to understand that.

Sir, I would like to make my comments about the functioning of the Akashwani. Sir, as far as the functioning of Akashwani is concerned, I am a little troubled by the kind of messages which are emanating from the Department.

मंत्री जी, मुझे यह कहने मे बहुत गर्व हो रहा है कि 'आकाशवाणी' भारत के विकास की वाणी है, आज देश मे 99 परसैंट कवरेज है, शायद 26 भाषाओ मे और 146 डायलेक्ट्स मे, तो आकाशवाणी ने भारत को जोड़ने का काम किया है, भारत को सूचना देने का काम किया है। आज भी जब मैं गांव मे जाता हूं तो देखता हूं कि शाम के 7:30 बजे बांस के एक खम्भे पर ट्रांसिस्टर टांग के लोग न्यूज सुनते हैं, हिन्दुस्तान के हर गांव में, चाहे वह बिहार हो या लखनऊ, हर जगह यही हाल है। हमे गर्व होना चाहिए कि आकाशवाणी ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन हुआ यह है कि इस टेलीविजन की भीड़ में 'आकाशवाणी' कहीं खो गया है, लेकिन हमे उसे भूलना नही चाहिए। माननीयं मंत्री जी, यह बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि एफएम चैनल का विकास होना अच्छी बात है, होना चाहिए। वह सूचना क्रांति और मनोरंजन का एक बहुत बड़ा उपकरण है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, आपने एक निर्णय लिया है कि चूंकि एफएम चैनल आ रहे हैं, इसलिए 'आकाशवाणी' के नए एफएम चैनल अब नहीं चलेगे। क्या मतलब है इसका? और संभवत: उनके 300 से अधिक ट्रांसमीटरों के सैंक्शन को रोका गया है। मुझे यह बताने की आवश्यकता नही है कि एफएम चैनल, जो निजी हाथों में चलते हैं, वे वही चलते हैं जहां मुनाफा होता है। होना चाहिए, हम उसके समर्थक हैं, लेकिन आप उसे और ज्यादा आगे मत बढ़ाइए। लेकिन जो आकाशवाणी का एफएम चैनल है, वह पहाड़ों में भी जाता है, गांवों में भी जाता है और वहां भी लोग आकाशवाणी के माध्यम से देश से जुड़ते हैं। Therefore, hon. Minister, don't weaken the Akashvani. That's what I want to tell you very clearly and if Akashvani is weakened, maybe, the country's link in itself may be weakened. इसलिए मैंने हमेशा इस बात को बहुत ही प्रामाणिकता से कहा है कि आकाशवाणी के साथ कभी-भी दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। मैं जानता हूं कि एफएम चैनल की ओर से यह बात चल रही है कि अब आकाशवाणी की जरूरत क्या है? यह ठीक नहीं है। आकाशवाणी ने इस देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है, इसलिए आकाशवाणी के विकास की तीव्रता को कम नहीं किया जाए। अगर यह विचार हो रहा है कि एफएम चैनल आ रहे हैं, इसलिए आकाशवाणी का एफएम नहीं चलेगा, मेरे ख्याल में वह टैंथ प्लान का टार्गेट है और पार्लियामेंट से उसको कंसिडर किया गया है, तो उसमें यह बदलाव क्यों किया जा रहा है?

माननीय मंत्री जी, मैं रेडियो की चर्चा के साथ एक चर्चा और कर रहा हूं कि एक कम्युनिटी रेडियो का कार्यक्रम शुरू हुआ था, अच्छा कार्यक्रम था कि गांव-गांव मे कम्युनिटी रेडियो आए, अच्छी संस्थाओं मे आए, उसकी एक अच्छी प्रतिक्रिया थी। मैं आपसे कहना चाहता

हूं, मेरे ख्याल में इस दिशा में बहुत प्रगति नहीं हुई है। कम्युनिटी रेडियो एक बहुत ही अच्छा उपकरण है, इसलिए मैं तो चाहूंगा कि उस पर आप और अधिक उदारवादी रवैया बरतें। अगर कोई प्रामाणिक एनजीओ इसे लेना चाहे, तो उसको भी बोलना चाहिए। Community radio is basically an instrument of empowering people by programmes which they themselves make. I regret to say, Mr. Minister, that community radio, of late, has got a pace which is not very happy. That's what I would like to tell you.

Now, let me come to Doordarshan. I think the observations I have made about Akashvani are equally relevant about Doordarshan. My friend, Mr. Shukla, was talking about various serials. He should not forget that television connectivity of India has also been made possible by Doordarshan, and most of the people, who are doing well today in private channels, had their training in Doordarshan. The irony is, others are flourishing. Why Doordarshan is floundering? It is a very important issue which we need to understand. I am informed that we have 24 channels. Out of 24, I would say, only three are doing little well. One is almost limping. One is DD-1, your shining symbol, then, there is DD News and then, there is DD Sports. Apart from these three, the condition of all others is very, very unsatisfactory. You have got about a good number of regional satellite channels like Oriya and Assamese. I understand that they are in a pathetic situation. And what troubles me, hon. Minister, is that Doordarshan revenue is rising. They have earned about a thousand crores of rupees. The total Budget is Rs.1800 crores. You say, there is no need for any support. I feel very strongly that the public broadcaster has a very great role to play in this country. Other private channels would always be inspired by profit motives, motives of TRP, motives of advertisement revenue. But the obligation to inform, the obligation to connect and the obligation to reform would always be by Doordarshan and Akashvani only. Therefore, the hon. Minister, I think, it is very important that these two public broadcasters need to be strengthened. Yes, they have to become competitive. Yes, they have to take on board professional approach. In many cases, it is lacking. Let us see where is the DD News. When it was started, its TRP was immediately after "Aaj Tak - Sabse Tez Channel". Today, where is that? You have a good news channel and you have a good body. I regret to say, Indian Information Service officers have a good role to play. They have done a good service. But the time has come that there should be a blend between professionals as well as Information Services people. That is not there. Mr. Minister, Yes, the Government is there, the Government news will be there, but let us not overdo it. Why I say so because, a couple of days

before, a young Member of Parliament made, perhaps, his second speech. It is very good. We appreciate it. But, on the DD News, I found a special programme, featuring the speech of that young Member of Parliament, and taking comments from the other Members as to how he has spoken. I think, this is a case of overdoing. I know there are good people, I know there are professional people, and let me tell you that DD News has a great role to play. Therefore, allow a blend of professionalism also there ...(*Interruptions*)... I am not yielding.

श्री राजीव शुक्ल : यंग एम0पीज0 को छोड़ दीजिए, हर नए एम0पी0 को दूरदर्शन पर आधे-आधे घंटे का टाइम दिया, बुला-बुला कर उसका इंटरव्यू किया। जिस यंग एम0पी0 की ओर इशारा कर रहे हैं, उनका तो कभी दूरदर्शन पर बुलाकर आधे घंटे का इंटरव्यू नहीं हुआ। हम एम0पी0 के बारे में, हर कंस्टीट्यूंसी के बारे में ये कह रहे हैं। अगर उनकी स्पीच में थोड़ा बहुत चला गया तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। आपने जो किया है, अगर हम बताना शुरू करें तो कहां से क्या हो जाएगा। दिन भर जो है...**(व्यवधान)**...

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): यहां यंग ओल्ड क्या हो रहा है...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0 जे0 कुरियन) : अच्छा बैठिए,...**(व्यवधान)**...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I still feel myself young. What is this? I am also young. Am I old? ...(*Interruptions*)...I may be very young. All MPs are young...(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Mr. Dipankar Mukherjee, Mr. Rajeev Shukla spoke because Mr. Ravi Shankar Prasad yielded.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I did not name anyone. My hon. friend, Mr. Rajeev Shukla, got up and made his point. His argument has been noted down ...(*Interruptions*)... My congratulation to him.

SHRI V. NARAYANASAMY: Because of your opposition.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, let me make certain comments on the larger issue of television. Mr. Minister, I hope, you will be very much knowing that close to 300 channels are beamed across the skies of India. One is the concept of down-linking. The other is the concept of up-linking. You have the facility of up-linking, but down-linking still remains largely unregulated. There is a cable connectivity. When I say so, let me remind you, and I am sure, you know it that we have got 8.2 crore television homes in India; we have got 4.4 crore cable homes in India. Therefore, if 5 persons are watching one television, let us take it that close

to 45 crore people in the country watch television. There is a very good connectivity. But, don't forget the fact that the rise of cable connectivity is very, very higher. The cable connectivity in Andhra Pradesh is nearly 80 per cent. Many other States have 70 per cent cable connectivity. Therefore, mere terrestrial reach of Doordarshan may come under serious attack. DD Bharati today has foundered completely, and you have a 'must carry' clause, which again will create a problem in future when competition rises.

But, having said so, let me pose two queries to you, in this connection. One is the television distribution, the other is the cable, the third one is the DTH. There is a consumer. Since CAS was mentioned, now, you will have to confront that problem. Let me share some of my views with you. The first and foremost concern should be of consumer interest. Our experience is that there is a lot of divide between the broadcasters, MSO and the cable operators. Let them settle their disputes. But, the consumer should never suffer, and television distribution should always be done with this fact in mind that the consumer will ask a question: "Why should I pay more to see less?" The Set Top Box will be an issue. Maybe, you have TRAI. Can you consult TRAI on this issue as to who will bear the burden of the Set Top Box price? There is a question of interrogability if a Set of Box is there. Let me tell you one thing. Television distribution in India is very artificial, and if this industry is growing, may I remind that 62 per cent of the turnover of this whole entertainment industry comes from television. Therefore, we have an obligation, you have an obligation to ensure fair distribution. He talked about the cable *mafia,* a whole lot of things. Transparency and accountability must come, and it must come with a focus on consumer's interest in mind.

Then there is the question of inter-operateability. If I have taken *The Zee* set-up box, will *The Star* accept it? Will *The Sony* accept it? These are the practical problems. The High Court has given you an order. I am quite sure you will certainly take all the stakeholders on board and come with a solution which is consumer-friendly. Always remember that any television distribution needs to be consumer-friendly. But, yes, you will have to go in that direction. When the DTH and TV divide is equally coming, people ask, when DTH is there, why should we be forced by a law? These are questions, which we will have to confront now. But DTH is not that sort of successful story. Doordarshan claims that it is KU band which has been a little successful. But the DTH story of 'Zee' is not that happy. Star is still to come about. I would like to know what is your DTH policy and how you

are going to properly combine cable and DTH keeping the consumer interest in mind. That is important.

The second issue about the television I would like to highlight, Mr. Minister, is that you have a Cable Act where under clause 6, you have got certain powers in what circumstances, a programme can be stopped only through the cable operator. We are all for a free press, we are all for a free media, we are all for free creativity. But, after all, the people who receive those contents have also got certain rights. To what extent they should keep on offending that by kind of programmes that are being made; I am sure, Brindaji will speak about this when her turn comes. I am only touching this issue in a manner that this needs some kind of intervention. I am against the Government intervention. But do you have some content regulator? It is high time that we need to have a proper content regulator. With 27 news channels, with so many other 24-hour news channels, so many regional channels, so many entertainment channels, the consumer of that, the viewer of that must have a voice, and that voice must be away from the Government. But there is a need for a forum. Therefore, I would like to know from you as to whether some kind of a content regulatory mechanism is under consideration of the Government or not. This question keeps on coming.

Mr. Minister, there is a very serious issue; I would like to say, here, about advertisements. Your advertisement code lays down the do's and don'ts. It should not be offensive. But why do we see daily those 'dirty' advertisements, if I may say so, from underwears to what not? We know that a liquor advertisement is banned. But we see on television आठ बजे कुछ भी हो सकता है, इसका क्या मतलब है? आठ बजे क्या होता है? We see some Star coming with a bagpiper soda water. Have you examined the advisement budget of soda waters or mineral waters? The real product may be of hundred crores, and the mineral water may be of Rs.10-50 lakhs, but the 'ad' budget is Rs.10 crores. This is a kind of hoodwinking being done to the people of India. Therefore, I say it is time to address those concerns.

Secondly,--I hope Kalrajji is here--we have seen together a programme. It was a very interesting programme going on, and there was a commercial break. 'It is not ending!' Commercial break, and it is not ending! Do you have some scheme in mind whereby an independent body lays down the do's and don'ts as to how many advertisements will be shown? A half-an-hour programme and a 15-minute advertisement! And that is all. Therefore, this whole business of TRP which we should not talk

of, needs some consideration because the entire reach of television is being considered upon the strength of a few meters being installed in selective towns. This TRP business is a murky business, I am sorry to say that because टीआरपी नीचे हो गई, तो विज्ञापन नहीं आयेंगे, टीआरपी को मैनेज करने के लिए विज्ञापन लाओ, गांव मे जाने की जरूरत नही है, शहरों में जाओ। This is a kind of situation which is not a very happy situation. Sir, I will take some time on films. I hope, I have some time, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): But try to be brief also.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Very brief. Sir, about the film part, I will say a few things. As was stated by the hon. Member, we make about thousand films. Let me tell you, you will experience, when you go abroad as I & B Minister--I am sure, you must have gone--that Indian films, today, are toasts for the world. People are looking towards India. Why is it so? We have got the young population. Fifty-four per cent of India's population is 25 and below. Therefore, the world is coming towards India because India has a big consumer base for entertainment. Let us utilise it properly. He talked about lack of capital. There was a scheme of Venture Capital in the films. What has happened to that? An expert body sat there. You need to bring in big business houses in entertainment and do proper financing of entertainment. I am happy that many big houses are coming forward. But the larger vision is that India has to become the hub of entertainment and need to be sold by you to the Prime Minister and to the Finance Minister. I agree that in the whole Budget the entertainment sector has not been given a very fair treatment. Mr. Minister, the Goa Film Festival came about. It is good. Please carry it forward. I don't think we will have pressures. I completely disagree. Take the State Governments on board. Goa has the potential to be the Canne of South-East Asia and people are responding. They have some personal knowledge about it. Make it a good content Film Festival, not a *Jhamura.*

Having said that, I would like to say one thing. When you treat the film personalities, you must treat them on the basis of their abilities, not on the basis of their affiliations. The reason why I am saying so is that a very eminent film personality of India was supposed to inaugurate the Goa Film Festival. At the last moment, he said, "No". I would say that it is the time that the I & B Ministry has a larger vision. The film personalities will have their own ideology and commitment. I am sure, Mr. Benegal is very much opposed to my party's ideology and he has got that right. But, I, as

a member of the BJP and as a Sangh Swayamsevak, always appreciated his films because they are fine films, they are creative films. This vision is very important because I have seen that for your Government the talent and creative potential of an actor is secondary; maybe, his affiliation is primary. That is not a very healthy situation, Mr. Minister. We need to treat him without discrimination, whosoever he may be.

Mr. Minister, a few more points I must register with you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): Mr. Ravi Shankar Prasad, you address the Chair, not the Minister.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, the hon. Minister is a good friend of mine. Therefore, whenever I see him I can't resist the temptation of addressing him directly.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIAN): The Chair is also your good friend, but impartial.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Vice-Chairman, Sir, the Indian music industry is growing very fast. You need to give proper input to it. Piracy is a big problem, both for film industry and music industry. Maybe, under the Copyright Act a provision is there that all the piracy will be handled by the Ministry of HRD. It is time to change it and get it back to the I & B Ministry because the moment piracy has become a problem, it has to be addressed in a comprehensive way by the I & B Ministry.

Sir, a few more observations about the print media and others. We are very happy that, regardless of the invasion of television, the print media in India is also growing. The rate of growth is close to five per cent. There was a feeling that when television would come, the print media would fall into the background. But I am happy to know that the newspapers are growing; the regional newspapers are growing. जहां तक हम लोगों का सवाल है, दिल्ली में अंग्रेजी में कितना भी छप जाए, लेकिन अगर कलराज जी और हम, बिहार और यूपी में, हिन्दी के अखबार में नहीं छपते हैं, तो शायद गांव में नहीं पहुंचते हैं। यह सच्चाई है कि आज गांवों में हिन्दी के अखबारों ने, रीजनल अखबारों ने बहुत बड़ा काम किया है। We want them to grow further. What is the further policy of the Government to encourage the great information revolution to happen in India? I would like to know that.

There are other issues of PIB and others. I would not like to go into the details. I would only say, you modernise them, you digitise them. The archives of AIR were supposed to be digitised. What has happened to

that? The archives of Doordarshan were in the process of being digitised. What has happened to that? Whenever we go to the Central Hall on the anniversary of any big leader, we hear the voice of that leader in the Central Hall. I would like to request the hon. Minister, please ensure that the voice of Jawaharlal Nehru, "The Tryst with Destiny", Subhash Chandra Bose, Shyamaprasad Mukherjee, Ram Manohar Lohia, Gandhi and Hiren Mukherjee, all these are available for the people in the market. They are all in the archives of the Akashwani. It will be a great thing. The same is the case of Doordarshan. They have got great footage which is being pilfered today. We need to properly digitise our great archives and archival record. This is what I would like to know from you. What further steps are you taking in that direction because information devolution is happening? Sir, recently, I had gone to Canada. We have co-production agreement with England, Italy and Ireland. They asked me as to what has happened with Canada. Why was it stopped? Canada has great potential of animation. They want to outsource it. Do you have proper training for animation in India because in combination with IT, animation has great scope? When I say so, I am very clear. Let there not be only Tom and Jerry. We have got our Panchatantra; we have our own folks. They must be shown to our children by way of animation. People are doing that. We need to encourage that.

Sir, the I & B Ministry has got great potential. I don't want to criticise them unnecessarily because I had an occasion to handle this Department. But I would like to say they have got immense potential, Mr. Minister. There is a need to have a proper policy initiative which propels growth. That is lacking a little. FM had to wait for one-and-a-half years to get computerised. These are the issues which need to be addressed properly. I hope the Minister will find some time from his pressing Parliamentary and Bengal commitments to give to the I&B Ministry. Thank you.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, in the House, today, we have present Ministers, former Ministers and would be Ministers. Subbaramiji, I am not looking at you. It is just a co-incidence that I looked at your side. We have producers, brilliant film directors, and brilliant actors.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): 'Would be' includes Shrimati Brinda Karat.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, thank you for your kind wishes. I just want to raise a few points, some of which have already been raised by hon. Shri Ravi Prasadji.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Ravi Shankar Prasad.

SHRIMATI BRINDA KARAT: I beg your pardon. रवि शंकर जब हम सोचते हैं, तो दूसरे रवि शंकर दिमाग में आ जाते हैं। माफ कीजिए, लेकिन फिर भी आप तो हैं ही ! Sir, when we look at the functioning of the Information and Broadcasting Ministry today, the first thing that occurs to us is that we are dealing with an age where information technology is hugely increasing its reach, its methodology and also its impact on people. So, naturally, in such a situation, where hardware itself is constantly changing in its reach and sophistication, then any regime which is concerned with the impact of what this can produce, necessarily, has also to deal with all the technological changes. One of the premises to be able to deal with this is a comprehensive policy concerning all the different spheres. For example, now there are technologies where with just one connection you can get a whole range of communication technologies. You have the Internet today and if you look at the regime for Internet monitoring regulation or even increase in India today, it is not at all addressing the basic issues which today Internet is creating. So, the first point that I would like to make here is, I believe, the lack of comprehensive policy in the Ministry to deal with the technological revolution, only some impact of which we are seeing in India.... and the inability to dovetail the different spheres of communication is leading to a situation where the consumer of these technologies is going to be the biggest sufferer both in terms of the content which is being propagated as well as the expenses of the technologies. So, the first question which I would like to address to the Minister is this. There are so many laws under his Ministry and yet there is no comprehensive policy for all these different spheres. So, is the Ministry planning to do this, now at least, under his able leadership? I do not know how many months it is now since he has been there as the Minister of I & B. In any case I think it is time to come out with a comprehensive policy for the different spheres. And, in this comprehensive policy, one very important point which we have been raising, and, I think, is a matter of concern, is the issue of FDI in the media. And, my party has been raising this issue from two or three angles. One is, we believe that today, given the impact of the different aspects of media, which I have already spoken about, and the ability of intervention and interference in determining the policies of any particular country, we

have to be extremely clear about what our policy is to be as far as FDI is concerned. Now, I think, the latest decision is that we are allowing FDI in scientific journals. There is also some permission given to foreign magazines to have Indian editions. What the contents of those magazines are, why we should give those magazines any type of permission at all, these are again questions which have to be addressed. So, the issue of FDI in print media, in television, in news channels, is, definitely, an issue which, I think, poses a wider concern which is also linked to the independent politics and democratic functioning of our various institutions. So this is another point which I feel the Government has to be more clear about, and we would welcome clarifications on what the Government's thinking is on this score.

The third point and, I think, this is very, very important, is that we are proud of the reach that we have achieved through Doordarshan and All India Radio. And, with all my strength, I would support the point which is being made by the previous speaker that we must give more attention to All India Radio. This is an extremely important medium of communication, of news, of entertainment, of information, of education, to the vast rural areas in our country. Therefore, whatever can be done to strengthen the All India Radio must be done and, I believe, that a much more developed programme, as far as All India Radio is concerned, must be made by the Ministry. In this connection, the whole functioning of Doordarshan is a matter of great concern. Sir, we have been stressing on the autonomy of Doordarshan, and because of the various struggles which have been raised by different sections of our population, to ensure that both All India Radio and Doordarshan do not become spokesmen or the mouthpieces of whichever party happens to be in power, we now have the Prasar Bharati Act which had been adopted, and the Broadcasting Corporation was set up under which autonomy was to be the key word. When I use the word 'autonomy', I do not mean autonomy *per se*; certainly, not autonomy from the point of Constitution of India, certainly, not autonomy to broadcast serials or films or programmes which belittle the secular framework of our country. Certainly not autonomy from basic human values. And, therefore, when we speak, my party speaks of the importance of the issue of autonomy, we speak of it in the framework of certain values. We have seen, Sir, over the years, the erosion of constitutional values of secularism, and I would also say human values. We have seen an erosion. I do not want to blame any one particular party. But, most definitely, during the years of the NDA regime, we did see a plethora of programmes which we believe did

weaken the secular ethos and secular framework within which any Government institution should function. Having said that, Sir, there is another aspect of autonomy which, we believe, and I don't want to mention any one particular leader or a young leader or whoever, but, the fact is that since the UPA Government has taken over, the issue of equal time to political parties, as far as reporting is concerned, the issue of equal time for achievements and also equal time for leaders, I am not just talking about a panel discussion, but I am saying even in the news, should be given. I can understand, where there is a Government programme, that Government programme must be reported. I am for it. I want that it should be reported because nobody else will report it. So, the Government programme is important. If the National Rural Guarantee Programme is being launched, I want Doordarshan to report it. That is very important. But, at the same time, the whole issue of projecting a particular party, a particular politician, a particular set of leaders which we are seeing repeatedly on Doordarshan is something which, I believe, goes against the principles of autonomy which are supposed to be cleared when the Prasar Bharati Corporation was set up and the Act was made. So, I would like to stress on this point. I know Doordarshan always gives lists of how much time is given to whom and so on, when these questions are raised. And, I am sure, the Minister will be able to supply that information. But, I do request him, Sir, to look at this with a little objectivity. I will request the Minister, I am sure he will be objective about it. And, particularly, now, Sir, since the elections are coming, since there are going to be big political battles which are being fought, it will be extremely unfortunate if the national broadcaster becomes just the mouthpiece or the agency to propagate any one political party's views. Therefore, I want to stress that in the functioning of the Ministry a proper understanding of the concept of autonomy is extremely necessary to strengthen democracy and democratic institutions in this country.

, I support, and my party has always supported freedom of expression. s is a constitutional right. किसी की मेहरबानी का सवाल नहीं है, it is our nstitutional right. Therefore, I always support it. I disagree with Rajeevji, en he wants a particular message only to be put in every film. Of course, is a very good film critic also. I have read many of his reviews. *nterruptions*)... You may disagree with me. But, yes. But, unfortunately, I cannot decide what kind of messages are to be put in all the films also.

I am for freedom of expression. But, in the name of freedom of pression, what is happening today is a national scandal. Does it mean this country's leaders and those who are running this Ministry have no

sensitivity to what women are feeling when they look at television, when they look at advertisements, when they look at remixes, when they look at the absurdity of the songs, when they look at the obscene gestures which are made and every single channel is showing it, including Doordarshan. Are women not human beings that they can be projected as commodities in the way that is being been done? I hold this their as the Government sole responsibility, in a legal sense. Of course, there is a social responsibility; there are social movements which are fighting this, which are confronting this. But, I want to ask the Minister how many people who are guilty of creating and broadcasting obscenity, when I say obscenity, Sir, I do not mean a woman in a swimsuit is obscene. No. There are different bench marks for it. But the question is the way the portrayal of women is demeaning, insulting and degrading to the independent citizenship of women. I would like to know from the Minister what action has he taken against these. Words are fine, "We will always support women's dignity." Women in this country are hearing these fine words for decades. But what is the action? How many people have been booked? Now, the Ministry has taken an initiative to have a regulatory code. What is the regulatory body? I would like to know whether that body is going to take action on the basis of the laws which already exist, multiple laws which exist in the country, but the laws which are not worth a scrap on paper on which they are written, as far as women are concerned.

Therefore, this is a very serious issue. I do not believe this is a women versus male issue. It is a question of the dignity of women, it is the question of upholding the rights of women as independent citizens. When I talk about degrading and demeaning I am not just talking about the portraying women in certain type of clothes and so on. Of course, that is very objectional. But demeaning I also mean, when you show woman only in a subordinate role, when you show a rape victim finding her salvation in marriage with the perpetrator of violence against her, when you show serials which actually promote female foeticide, these are as demeaning as anything which can be considered obscene. I believe, in fact, in certain ways, these are even more obscene.

Therefore, a code which is already there in the laws of this country, we would like to know from the Minister, what is the regulatory mechanism which is going to be set up? Are women going to be equal participants in it? Are they going to have any say in it? I am sure, the Minister will say, 'yes'. But I would like to know within which time-frame it is going to be set

up and how is it going to be implemented. This is the other point I wanted to make.

Apart from that, Sir, we are extremely concerned about the situation of employees of these corporations. I may, Sir, add as many sections of media, as far as newspapers are concerned, as far as other television channels are concerned. Now, as far as Doordarshan, All India Radio and Prasar Bharati are concerned, I have had so many complaints from many of the employees, as far as their conditions of services are concerned. They have had so many complaints and unfortunately, till now, the Minister has not had any dialogue with them. There are a large number of women who are employed in these. I have had complaints from women employees who are performing extremely difficult role, in most difficult circumstances and yet, according to the reports that I have had, the mechanisms as far as complaints of sexual harassment are concerned, they do not exist in a proper way, according to the Visakha guidelines, as far as these corporations are concerned.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Your party had 11 minutes and you have taken 16 minutes.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, I am not going to take much more time. I just want to say that it is extremely important that you treat the employees properly. When you talk about the Ministry of Information and Broadcasting, I want to reiterate the responsibility of the Ministry has towards its own employees who are trying to compete and in looking after its own employees, I believe, the institution itself will be strengthened. So, this is another area to which, I think, more attention has to be paid.

I would just like to draw the attention of the hon. Minister to a fact, and I am sure he is already aware of it, that in large areas of the country, including in the capital of this country, you have very successful newspapers who have now contractualised all journalists. The most senior journalists in some newspapers are now being asked, you either sign this contract, which basically make you a bonded employee of this newspaper, or you can quit. Now, a person who has worked for 15 years in a newspaper, does he or she have any choice? They will have to accept that contract. Therefore, whether you have labour reform or not, in actual effect, in such an important industry, the processes of labour reform are already taking place at great cost to the rights of the employees and workers in the industry of the media. I know this comes under the Ministry of Labour. But I want to

request the Minister, please do not remain a mute spectator to the decimation of workers' and journalists' rights in newspapers, in print media and in the electronic media today because if you remain a mute spectator to it, then you are not going to be able to compete in a world in which satellite channels are posing the greatest challenge to our own indigenous channels and our work. Finally, Sir, I would like to request the Minister to come out with a policy as far as films are concerned. I am not talking about the big Indian film industry. There are many spokespersons here who will raise the problems I am sure and I support them, but I would just like to talk about documentary film makers. Now, in India, unfortunately, the kind of attention that should be given to documentary films is not being given. It is most unfortunate situation that some of our most talented young people who are coming out of the best such institutes, they have to run around to different funding agencies, including American funding agencies and other funding agencies to get some amount of money to make documentary films. I think this is very unfair and unjust because there is so much to be documented in this country, there is so much to be said in this country and there is so much that this country through documentary films can tell the world. And because there are young people, there are no strong vested interests and there are no strong lobbies which are making money out of it, therefore, we do not hear their voice at all. I was extremely distressed to find that in some documentary film festivals in this country, I was told, there were double standards that there was no censorship required for some of the foreign films which were coming, but as far as Indian documentaries are concerned, they have to go through censorship. As far as documentaries are concerned, this is an area where self-certification is something which should be accepted. It is important because if we start censoring documentaries, and my friend Rajeevji was speaking about a message which has to be sent, very often, documentaries in fact, epitomise social realities, and, therefore, automatically their messages are sent. Therefore, on the one hand you want to send a message; and you want to censor that message, then that is something, Sir, which I think does need to be looked into. Therefore, I will request the Minister to kindly look at this whole aspect of documentary films and to give documentary film makers the support of this Government, the support of his Ministry, not just morally, not just through looking at the censorship rules, which should not have double standards, but also financial support. I am sure, Sir, that in the coming days, the Minister will address many of the issues that I have raised. Thank you.

4.00 P.M.

SHRI SHYAM BENEGAL (Nominated): Thank you very much, Sir. I think I have jumped the queue, as a matter of fact. I will only make a very short intervention really. I will restrict myself to cinema largely because you see there has been a lot of discussion here about the Indian film industry and the fact that it has enormous growth trajectory, which it is, because I can tell you straight of that three billion nine hundred million tickets are sold for Indian films every year while for Hollywood films, there are only three hundred million tickets are sold. There is a huge difference. It does not show itself in terms of revenues because our ticket prices are very much lower and the American films, of course, are two hundred to three hundred per cent more than our films do. Now, I do not personally believe that the Indian film industry because it has been doing brilliantly over the last 100 years. There have been blitz from time to time but the most important thing, of course, is that it does not necessarily need any kind of support from the Government. What it does need is the punitive tax system, the entertainment tax regimes in various States. I don't know how the Centre can help here because this is where that must come down substantially if the film industry has to properly prosper. Secondly, there is another problem here, which has to do with the fact that our film industry, which is a new phenomenon and has started over the last 15 years, is that of piracy. Piracy is one of those aspects, which eats into everything. It is one of the most dreadful things that have happened and we do not have any kind of proper legislation on it and certainly the Executive does not seem to help in this process. These are the two essential things that the Government should take serious steps about it. As far as the third thing is concerned, which I personally believe is very important, is that many years ago in the 1960s when Mrs. Gandhi was the Information and Broadcasting Minister, one of the things that was done was to encourage film making and that kind of film making which really meant to use cinema as a catalyst for social change. This is a concept which did create, in a sense a certain kind of movement. Now, obviously, when you make films of this kind, when the film industry functions in a *laissez faire* situation and it is dictated entirely by the market, there are lot of young film makers who want to make films that function as a catalyst of social change but they cannot possibly do that because nobody is going to fund them. Now, we used to have a mechanism of the National Film Development Corporation, which alas does not really exist anymore. There is a Bill; I saw of the National Film Development Authority, that Bill is apparently going to be placed on the

Table. Now, there it is very interesting to see that you are going to have a recurring expenditure of Rs. 2000 crores which is a wonderful sum of money when it comes to that, but I would not like to move into an area where films are already being funded beautifully and why that needs any kind of support. It does not require any support. What we need is, the needs for creative expression through the cinema is an area that is felt not only by the Hindi film industry which is the Pan Indian film industry and is the most successful among all the regional film industries of the country but it is required in areas, particularly I would imagine in areas where the need to make films exist but there is no critical mass of an audience like the North-East. If you are thinking in terms of Manipuri films, the Manipuri films cannot possibly pay for themselves. There are other areas in the North-East similarly or in the South for instance, there are filmmakers who would like to make films in Tullu and Konkani. But you do not have the critical mass of an audience for films of this nature. But, this does require support. This kind of thing is very important and I do believe if that Bill ever gets passed and something happens there, there should be an ideological position that the Ministry should take in terms of supporting films. That is one aspect of it. The other one, of course, is in terms of censorship. Mr. Rajeev Shukla talked about censorship. I totally disagree with that concept. I personally believe that censorship is a matter where the industry itself must create a self-regulatory mechanism. I have been saying this for years and years and years. There has never been any serious attempt to do this because unless that happens, I do not believe that the Government should be actually sitting there and censoring things and imagining that it is working towards social good. It doesn't work towards any kind of social good. It is a negative instrument. It is meant to curb things. It is not meant to encourage anything. So, the censorship, in fact, simply does not work and I do not believe any attempt should be even made to re-work the censor code because ultimately we have the Constitution of India. Whatever we do has to be within the parameters of the Constitution of India. And, it is the same thing when it comes to cinema or television or whatever.

Sir, the other point I wish to make is about television itself. Comments were made that there was a time when Doordarshan was producing exceptional programmes. I agree with that. There was a time when Doordarshan made exceptional programmes, because, at that time, Doordarshan was the sole broadcaster or telecaster in the country. When private telecasters come, Doordarshan, for the reasons best known to itself, decided that they should go on the basis of creating TRPs for themselves.

Without, for a moment, considering it self as a national telecaster, you have a social obligation to the people of the country. You are not in it to make business. You are not in it to make profits. It is not the purpose of Doordarshan. It is not the purpose of the AIR. Doordarshan, essentially, has a very strong social role to play and that is what they should concern themselves with. Therefore, if they have to be involved in any kind of artistic thing, it should be on the basis of giving full play to the quality of work that is going to emerge, and not worry about whether they are going to compete with private telecasters.

Now, basically, these are the points I really wanted to make. Thank you very much for giving me this opportunity.

SHRI C. PERUMAL (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to speak on the working of the Ministry of Information and Broadcasting. Today, with the advent of latest and new technology, television industry has grown manifold. Now, we are able to watch more than 100 channels, including foreign channels. While the growth is welcome, yet, this growth is unregulated.

Sir, I want to drive home the point that the growth of television industry has not been put to best use. I also welcome the growth of radio industry. Now, a listener has an ample choice.

I take this opportunity to bring to the kind notice of the Government the rumours spread by one private channel in Tamil Nadu. The channel is owned by family of a coalition partner of UPA Government. This channel is dead against the Government of Tamil Nadu. This channel spreads false news, rumours and always gives incorrect and incomplete information.

I wish to recall here the relief and rehabilitation measures undertaken after Tsunami by the Government of Tamil Nadu. It was appreciated not only by the hon. Prime Minister, hon. Home Minister, but all other dignitaries. And, there was also appreciation at the international level. The former President of the USA, Mr. Bill Clinton, also appreciated the Government of Tamil Nadu. In fact, Sri Lanka and Indonesia, which were also affected the worst by Tsunami, requested our Tamil Nadu Chief Minister, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, to depute the officials to work in connection with rescue and rehabilitation after Tsunami in their respective countries. While the whole world appreciated the efforts made by the Government of Tamil Nadu after Tsunami, this television channel gave

concocted news about the measures. The people of Tamil Nadu were happy about the measures undertaken by the Government of Tamil Nadu. They got their food, housing and other relief materials on time and also assistance for self-employment, fishing nets, etc. It is another story that the Central Government did not help at all.

Not only this, anything done by the Government of Tamil Nadu, the channel always twists the fact and gives false news. If the Government of Tamil Nadu announces any welfare scheme, the channel always gives incorrect and incomplete news thereby people get confused. Last year, the State witnessed unprecedented rains causing havoc and floods in the majority of the State. The State machinery swung into action and took necessary steps for rescue and rehabilitation of victims. But this channel, true to its word, telecast some old pictures to make people believe that the Government did not do anything. Not only this, this family has a newspaper which also spreads false news. During the floods last year, when every channel, newspaper put the death toll correctly, this newspaper indiscriminately and falsely increased the toll and thereby created panic and confusion in the minds of gullible citizens.

Not only this, only this channel telecasts advertisements of the State-owned telecom companies and other channels cannot telecast them. In fact, a case been filed against this channel for this act. All the advertisements of the telecom companies are telecast by this channel because the Minister-in-charge of Communications happens to be a member of the family that owns this channel. This channel violates all the professional and ethical codes of conduct of television industry.

Sir, I strongly demand that a severe action should be taken against this channel and the newspaper. In fact, I strongly believe that the licence of this channel should be cancelled forthwith and actions be taken against the owners of the channel. What I am mentioning is all about the Sun TV, the Dinakaran, the Tamil Murasu and the Murasoli. ...*(Interruptions)*... Sir, while coming to the working of the Ministry..*(Interruptions)*... Sir, I may be permitted to continue my speech. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. SHUNMUGHAMSUNDARAM (Tamil Nadu) : Sir, this is totally ...*(Interruptions)*... This should not be allowed. ...*(Interruptions)*...

SHRI C. PERUMAL: Sir, I am just mentioning what is happening in Tamil Nadu. That's all. ...*(Interruptions)*... I am providing a true picture of what is going on in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. SHUNMUGHAMSUNDARAM: Sir, he is naming some private T.V. channels. ...(*Interruptions*)... This is unwarranted. ...(*Interruptions*)...

SHRI C. PERUMAL: Sir, I am giving a true picture. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): What is your complaint?

SHRI R. SHUNMUGHAMSUNDARAM: Sir, he is making certain allegations against a private T.V. channel. This is not a forum to complain about a private ...(*Interruptions*)...

SHRI C. PERUMAL: Whatever I am mentioning is true. ...(*Interruptions*)... It is a fact, Sir. ...(*Interruptions*)...

SHRI R. SHUNMUGHAMSUNDARAM: Can we debate this? ...(*Interruptions*)...

SHRI C. PERUMAL: Sir, while coming to the working of the Ministry, I strongly believe...(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) : Mr. Perumal, you speak generally, not on a particular T.V. channel. (Interruptions) I will look into the records, if it is anything against the rule, it will be expunged. ...(*Interruptions*)... Mr. Perumal, you say whatever you want to say, but you are reading a speech written by somebody else. It is not good. Or, you lay it on the Table of the House.

SHRI C. PERUMAL: Sir, what I am reading, what I am speaking, is all fact. ...(*Interruptions*)... I am not giving any false views. (Interruptions) I never give false views. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) : No, you can refer to the notes and speak. But you are completely reading. ...(*Interruptions*)... Listen! I was watching you. You were fully reading right from the beginning. This cannot be allowed. ...(*Interruptions*)... You can refer to your notes. ...(*Interruptions*)... Please sit down. I will control the situation. ...(*Interruptions*)... No, no, please sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI C. PERUMAL: Sir, my good friend is...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) : Mr. Perumal! ...(*Interruptions*)... Mr. Perumal! ...(*Interruptions*)... Mr. Perumal, you should observe the ...(*Interruptions*)... You address the Chair. (Interruptions)

SHRI C. PERUMAL: Sir, he is ...(*Interruptions*)... He looks only...(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) : You address the Chair. But fully reading and only reading the speech is not in conformity with the rules. That's what I am saying.

SHRI C. PERUMAL: Okay, Sir. I come to the working of the Ministry. I strongly believe that there should be an inbuilt mechanism to take note of such instances and take action. Many companies and many channels have applied for starting new channels and also to expand their channel's network. I demand that the Government should take urgent steps in this regard.

Another important aspect is facilities to small and medium newspapers. They find it difficult to get newsprint at subsidized rates and on time. They should be given all facilities. A comprehensive policy in this sector is necessary. Another important aspect is that the welfare schemes announced by the State Governments should be given wide coverage and, in any case, it will benefit public only. For this, the press and information offices in the State should be directed to take necessary steps. Sir, I also demand that a broadcasting policy should be formulated at the earliest. I also take this opportunity to request that adequate staff be allotted for the Doordarshan studios at Madurai and Coimbatore. The existing vacancies in All India Radio stations in Tamil Nadu should be filled up immediately. FM channels should be started in Tamil Nadu wherever required. In my district Krishnagiri also a Doordarshan Kendra should be started.

In Dharmapuri district of Tamil Nadu, the All India Radio station is yet to be inaugurated because sufficient number of employees are not there. So, it has to be taken into consideration by the hon. Minister.

Sir, with these words, I conclude my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Thank you Mr. Perumal for sticking to the time. Smt. Jaya Bachchan.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I waited for many months to speak on this subject, and I am so glad that today I got the opportunity. What I am going to say is not going to be very technical because so many technical points have been brought up. And, I feel a little awkward to say and make certain points in front of a Minister who has taken up the portfolio a few months ago. And, I do not think that would be very kind to him. I have very, very strong views on this. But, I will not impose those on you, Sir. This is a very, very important Ministry, especially, today. And, when we decide on who is going to be looking after the Ministries or different departments, we pay a lot of attention to the fact that the person who is going to be heading it has a certain technical background. With due respect to you, Sir, I think, you would require some more time to understand the functioning of this Ministry for you to really, convincingly answer all the questions that are going to be asked. Fortunately, for you there are not many people. You have just heard the former Minister of Information and Broadcasting, from the previous Government speaking. He has got his points absolutely right. I have had the privilege of working in an autonomous body with the I & B Ministry in the past. So, I have certain knowledge, and whatever I am going to say will come from that. I have written some points, I will refer to them. I am not reading them.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): You can certainly refer to it, there is no problem.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, the most important thing is, this is my personal opinion, I do not think that the Government should be in the business of entertainment. It is not their job. The Government should be governing. The Government does not have the knowhow of competing with the entertainment business because it is a very highly competitive business today. All the agencies run by the Government or handled by the Government were established years ago by visionaries, by leaders who had a certain vision. They started certain activities and those activities have been throttled after the country started progressing and developing and these visions went into the background. Therefore, today I do not think the Government should be in the business of entertainment because if the Government gets into the business of entertainment, they will neither be here nor there. This is the only Ministry, I feel, which has no accountability. For years together, this Ministry has been functioning. They make rules; they don't make rules. They follow rules; they do not follow rules. There is

no accountability. Because, this Ministry, in public perception, is good only for media. What is conveyed through television or through radio is what this Ministry does, but that is not true. The Ministry has a lot of other things that it does. The television and the radio that this Ministry has under its portfolio are managed, but it is not up to the standards of the rest of the other Television channels or the other private radio channels. Therefore, they fall short. Because, again, being in the Government, you don't know whether you should be out and out commercial, or, you should talk about the country, the development and informing the people about the achievements, or, what the Government is doing. So, there is a bit of ambiguity there. So, there is no answerability; and, that is a huge problem. There is no vision. I do not blame this Government. I do not blame the past Governments. I blame all the Governments which have come and gone, that there was a vision when it started out, but, later there was no vision. They were only managing, and, very poorly. One of the most important activities that the people know about the Information and Broadcasting Ministry, for example, is Doordarshan. It is wonderful. I don't want to talk about the way the Doordarshan functions, the way things happen...(Interruptions).. Pardon me.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA (Karnataka) : It is doing well.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Doing well. Well, I don't want to talk about TRPs, because, just recently, some TRP reviews were given. So, let us not get into that discussion. But, I don't think that they are doing well. I think it is shoddy. It has no vision. It does not even have glamour that it pretends to have. I am sorry to say this, but this is the truth. We have to get a little objective. I am not blaming any individual, I am not blaming any party. I am talking about our lack of interest in the Department. Let us take Doordarshan. Whatever they show, is that good enough? The telecast quality is very poor. It shows, our attitude towards the channel. Something that you can't see well, you don't want to see. There are other channels which are giving you information, a lot more *masala,tf* that is what people like. So, that is, I think, shoddy. I am going to speak not superficially, but superficial level, because I don't want to go into details., I think there are very serious questions that one needs to ask the Information and Broadcasting Ministry, and, for that the Minister should have been in the job for a longer time than he has been. Why is it that when we watch Doordarshan, we feel that we are trying to compete with the English speaking channels. That is not necessary. आप हिन्दी में बोलिए या

किसी भी हिन्दुस्तानी भाषा में बोलिए, अच्छे से बोलिए, गर्व से बोलिए और सुंदर से बोलिए। मगर हम जो न्यूज दूरदर्शन पर देखते हैं या दूरदर्शन पर कोई भी प्रोग्राम दिखाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सब-स्टैंडर्ड क्यों है ? बाकी चैंनल्स के कम्पेरिजन में कम क्यों लगता है, छोटा क्यों लगता है और उतना अच्छा क्यों नहीं लगता है? इन सब पर विचार करना बहुत जरूरी है। Because it is a visual medium, and the visual medium, if it is not clearly -- and by 'clearly', I mean, 'clarity', I am not only talking about glamour and the glitz -- shown, it is not going to be effective.

Sir, under the I&B Ministry, we have the NFDC, the Films Division and the Children's Film Society. I have had the honour of being with the organisation, the Children's Film Society, for ten years. It was an autonomous body, and, as always, it was an honorary job. *...(Interruptions)...* No; Sir, I don't like to hold offices of profit.

Sir, the NFDC, when it was visualised, was a wonderful concept, and every developing country has an organisation like NFDC. But what has happened to it? I just want to ask you that question, and I will leave it at that because, your answer to the House is good enough to tell us what is happening with the NFDC. The Films Division, a wonderful organisation --what has happened to it? We have thousands, thousands and thousands of reels of fantastic documentary, documentaries on national leaders, national monuments, etc.; I mean, that organisation has done an amazing amount of work. What has happened to it? Where is it? What is the upkeep? I just want to ask that, you can answer that.

Sir, then I come to the issue of Children's Film Society, one of my pet subjects. The Children's Film Society is an autonomous body. Do we need a Society like this today? What is the work that the Society is doing? What is the kind of money you are giving to the Society? Is the money that you are giving enough? Please answer. I am not going to elaborate on it.

Now, I take up the issue of film censorship. Sir, if you ask me personally, I think, it is a shame that this country should, still have film censorship. We are adults. The film industry is an adult industry. The film industry is functioning on its own without any support, any help of the Government. Why control? When are we going to stop controlling 'creativity'? Please control, but stop controlling 'creativity'; stop this word 'control'. We are adults; let us function like adults. Let our minds think independently. Please do not tell us, and I am not talking about only the film industry, I am saying it in general. I don't think we need a Film Censor Board. The industry is old enough and the industry is very answerable, and

if people find certain things objectionable, do not go and see it. The censorship has to be within us and not to come from outside. ...(Time-bell)... Sorry, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): Try to be brief.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: We are so used to the dialogues being written for us and reading those lines written by somebody else. Reading your own lines take a little longer.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN) : But you are making very strong and bold points.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I am just asking for a little bit of sense of humour.

Sir, again, I am going to say what my other colleagues have said earlier. Piracy is a huge problem. One day the film industry people are celebrated as the highest tax-payers in the country, and the second day, you have Income Tax officials raiding them, asking how they paid so much tax; from where they got that much money? These are very, very funny issues. But, on piracy, there was a survey conducted in Maharashtra, in Bombay alone, about three years ago, where they said that in one DVD theatre, that is, in a small *jhopdi*, there are a hundred people who watch pirated DVD films, who are charged Rs. 10 per person. Mind you, it is a DVD print. So, they have hardly spent any money on it. There are, at least, five shows with five hundred people watching, who pay Rs. 10 each, and this is only in one *jhopdi*. There are 10,000 such places where people show pirated video films. Government is losing revenue; we are losing revenue. I am not saying that you can completely stop it, but what are you doing to control it? You need to take very, very strong action.

Forget about films, what about audio piracy? In our own country, there are places where there is audio piracy going on. It is shocking. If you go to the markets in Delhi itself, you would see audio cassettes being pirated and audio CDs being pirated. And, if you ask me, I think the way remixes of classic songs of cinema is done is also an act of piracy. It is somebody else's idea, somebody else has thought of it, somebody has sung it, somebody has directed it, somebody has acted in it and some one else is distorting and pirating it. That is what it is.

Sir, there are lots of questions to be asked, but I hope we get the opportunity to ask more questions another time and we can get into a bigger debate. But I would be very, very happy if you just answer certain specific questions that I have asked. Thank you very much for your time.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Thank you, Vice-Chairman Sir. This particular subject has given rise to a lot of discussion. As a member of the Consultative Committee on I&B, I have seen that within the last seven years, seven Ministers have been in-charge. During the NDA regime, in four-and-a-half years, there were five Ministers in I&B. As the hon. Shri Ravi Shankar Prasad was saying, he also held additional charge of the Ministry of Mines and Coal and he could not fully concentrate on the I&B Ministry. Though he was a very dynamic Minister of that time, he could not deliver on certain things. Therefore, he has said many things here as advice to the present Minister.

Sir, we have great hopes from the present Minister, Shri Priya Ranjan Dasmunshi. He is a very good football player, a very brisk and dynamic person. Therefore, he should not be treated as a ball...(*interruption*)...I am coming to the point. It should not be like the many stars and positions that are thrown just like a ball in the I&B Ministry. It should not be like that. At the same time, it is high time to think whether we wish to continue with the Prasar Bharati Act or not. We need to think whether in this Act -- we should not use any unparliamentary word -- there is some duality. On the one hand, you want to give autonomous status to the I&B Broadcasting Ministry, that is for Radio and for Doordarshan, on the other, we are requesting that more time should be allotted for political parties and more news should be given for that aspect. That means, you are curtailing the autonomous status of the Prasar Bharati. If you want to make it a corporate body, make it a corporate body. You should not deal with that corporate body. They should work as a private channel. They should compete with the private channels. They should have their own policy; they should have their own trade policy; they would have their own commercial policy. They should charge according to the market. Are we doing the same thing for the past decade? We are having a duality. We want to say that Prasar Bharati should be independent, but, at the same time, we have not yet decided about the Government staff which was there, at that time, as All India Radio staff or Doordarshan staff. Even now, they have not been merged with the Prasar Bharati. Many of the people who were working as a Programmer, as a Technician, as an administrative staff,

have never got any promotion in the last 16 years. They have never got any other thing in their life. How can we expect that particular staff to be imaginative, to have the competitive edge over other private channels? But, even then, they are doing well. Even then, they are competitive. Even then, they have got all the qualities to compete with the private channels. I am dare enough to say that if you want to get the truth of a news item, then, you have to go to the Doordarshan or the All Indian Radio. You cannot get the truth in any private channel. They just blow up the issue. For example, in the morning, we may be having some issue due to which session could have been adjourned. But, the private channels telecast that the Parliament is rocked; the people have stopped it; the Parliament is adjourned. But, afterwards, we again convene. We do the business. Are they reporting it? But, the Doordarshan and the All India Radio report that there were discussions, that there were enactments of the Bills; that many of the things were done in the Parliament. In this way, damage control is done by the Doordarshan and the All India Radio. Therefore, I request that we should take a clear view whether the Information and Broadcasting Ministry should have the All India Radio and the Doordarshan as a wing of the Government or not. It should be like that because we cannot go on competing with the corporate bodies. Sir, on the one hand, some Members are saying that the Government should not go for commercialisation of these bodies; these should be service-oriented; these should have a social obligation. And, on the other hand, they ask the Government as to why it is not giving them so much of funds. How to give them funds? Therefore, they should be purely under the Government machinery. They should propagate and telecast what is happening. Today, both the Houses of Parliament are on the AIR. Doordarshan is telecasting the proceedings of the Parliament. Can NDTV or any other private channel telecast this throughout the day? They cannot do it. It is not commercially viable? But, Doordarshan does it. Therefore, there is a loss for the Doordarshan. Now, Executive action, that is, what the Prime Minister or the Ministers are doing every day, or which foreign dignitaries are coming, or what are the agreements entered into by them - all these things are telecasted by the Doordarshan and broadcasted by the All India Radio. Are private channels doing it? Have people got knowledge about it? People have knowledge that Varanasi is in the ethnic trouble; another party is going on Rath Yatra. That is the kind of telecast that is going on. That is the business they are doing. That is the emotional thing they want to show. But, Doordarshan gives the clear news. It gives the position of both sides -

the Opposition and the ruling party. News relating to both, the Opposition and ruling party, are shown. It should be a part of the Government. That is my submission. I was a Member when NDA was in the Government. At that time also, I told that Doordarshan and All India Radio should give the Government programmes in a proper perspective. I conducted a multi-media campaign, even though I was sitting in the Opposition benches at that time. I conducted campaign about the Government programmes being implemented through different Departments. That was made as a multi-media campaign in my parliamentary constituency at that time and people were awakened. They were told that these were the programmes through the Government, through the banks, through the insurance companies. I can conduct the same thing now as the Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Public Grievances. In 22 parliamentary constituencies in Tamil Nadu, we have conducted this multi-media programme through the I&B Ministry. The entire staff committed themselves. They have got the patriotism to say that this is the Government programme; for the people, we are bringing it. This is the product that people are getting. This is the service the Government is giving to the people. Are the private channels telling this thing? Sir, some of the hon. Members were speaking about the National Rural Employment Guarantee Scheme. Is the NDTV, Sony or any other channel telling about it? They will highlight only if there is an error or if anything wrong happens. But they will never propagate the scheme that one can go and get the job; and the job is assured. And, even if one does not get the job in 15 days, salary will be given to the person who has enrolled himself under this particular Act. This was shown or depicted by Doordarshan, by All-India Radio throughout 24 hours, and, thus, a good message is delivered. For various Health programmes, Rural Health Mission, who is propagating and telling the people? None of the private channels is telling about these programmes. Only Doordarshan, All-India Radio and the media supported by the Government are telling that. Therefore, this thing is for the people and, so, we cannot expect to have special things from Doordarshan.

Sir, some Members have spoken about sex depiction, vulgarity and others things. Sir, you can see nothing of this kind on Doordarshan or in All-India Radio. They are doing everything properly and according to the rules. Therefore, I request that the Government should take a decision to repeal the Prasar Bharti Act and say boldly that this is a part of the Government machinery, it is for the people, it is for broadcasting the Government programmes.

Sir, further I would like to say that Songs and Drama Group, the field publicity department, the DAVP, all these departments are doing wonderful job. But the Government machinery is not at all properly using them. Sir, the hon. Finance Minister is not here.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): The Minister for Information and Broadcasting is here.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Yes, Sir. But he has to again speak to the Finance Minister. We are pleading to the Finance Minister to allot more funds for the I&B Ministry. This is the only Ministry that can propagate the entire work of the Government machinery. Sir, a statement by the Finance Minister can be broadcasted on Doordarshan. The other TV channels will broadcast it only for a particular group of people who want to have that message, not for the poor people.

Sir, Doordarshan should be fully equipped by the Government money. All the public sector undertaking -- be it banks, insurance companies or any other public undertaking -- should spend, at least, 10 per cent of their publicity expenses in favour of Prasar Bharti, that is, Doordarshan and All-India Radio. Thus the financial crunch will not be there. They are unnecessarily paying to the other channels, which are not at all telecasting anything about the Government programmes. Sir, the culture and tradition are being taken care of only by Doordarshan and the Songs and Drama Division. They are carrying various messages to the people, to the ordinary people who are not even having a television, and, who look forward towards the Songs and Drama Group. The village people can understand things in a better manner through the dramatised programmes performed by the artistes or the village people. They are also getting jobs by these methods. There are poor people, the artistes, who are traditionally dependent on this Songs and Drama Division. These people are not offered these things by any other agencies, and, only the Songs and Drama Group, a part of Ministry of Information and Broadcasting, is doing this work by giving jobs to poor people. They are also doing the job of retaining the culture. I would like to stress upon the aspect of looking into the grievances of the Government staff in Prasar Bharti and also in the I&B Ministry. There should be immediate redressal of the grievances. There are many examples. I need not cite any particular case. A very good producer who is part of the Doordarshan, she faced sexual harassment by one of the persons in the staff ten years ago. Even till today, she has not got her salary. This is the kind of redressal mechanism that is working in the department. In the

same way, there should be a proper policy for promotion for everybody. There should be absorption of the cadres. There should not be any differentiation between the technical, administrative and the programme executives, and, there has to be an appropriate convergence of all those people. Then, Sir, I request that if the Government wants to retain Prasar Bharati, there should be total independence for All India Radio and Doordarshan to go commercially. They should earn money. They should earn money just like other private channels are earning. After the hon. Minister has taken charge, he has earned a huge amount of money for the Department, for the Government, through selling the slots for the FM bidders. So, that sort of earning should be utilised for equipping this Department.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

Then, Sir, there are Doordarshan Kendras and All India Radio Kendras which were built up during the Ninth Five Year Plan. They were fully equipped with the cameras and all the machinery. But, they do not have the human resource. They do not have the technical personnel. They do not have the programme executive. I can cite the example of Madurai, Coimbatore and Dharmapuri. These are the places already built with huge money. Crores of rupees were spent. But, they are locked up now. The Director of the All India Radio, Madurai, is looking after the Doordarshan also. There is no man to man the Doordarshan Kendra. The same thing is happening in Coimbatore. The same thing is happening in Dharmapuri. We have requested and our hon. colleague, Mr. Shunmugasundaram, has raised the same issue when the Finance Minister was there. He assured that it is not stopped on his part. But, I am very sorry to say that the Finance Minister should also clarify why the files are not cleared by the Finance Ministry. As I have heard in the reply of the hon. Minister, the recurring revenue losses should be curtailed by way of reducing expenditure. Sir, I request that whatever money, even one rupee, is spent for the radio and Doordarshan, that is for the welfare of the people and for the welfare of the Government. Therefore, there should not be any crunch for that. The Finance Minister should give more grants. Rs. 80 crores or something like that has been given in the Annual Budget. It is a very, very meagre amount. Thousands of crores rupees should be given for this Ministry. Then only, the people can be educated. They can be aware as to what is the programme. I want to give one small example, Sir. I wanted to make the same thing when the Finance Minister was there. But, I am making it

now. There is one product in the public sector, that is, general insurance. If a person pays Rs. 15 per year, he gets Rs.15,000 worth of medicine and health care in any of the topmost hospitals, like, Apollo and all that. Another programme is there that if Rs. 365 are paid per year, and out of that Rs. 200 are paid by the Government of India and Rs. 165 are paid by an individual, medical care of Rs. 30,000 is available for the individual. Except the multi-media campaign, except the I&B Ministry, except the Doordarshan, except the AIR, will any other channel in the world or in India broadcast this thing? Whether they tell this message? Whether any one paper will tell this? They will not tell this because they are not for the *aam aadmi*. They are for the rich people. They have their own commercial aspects. But, Doordarshan and the AIR can tell this. People can be benefited by them only. So, Sir, the Finance Ministry should look into it. If they are spending about Rs. 6,000 crores for Health Department, let them spare, at least, Rs. 100 crore for this purpose so that ordinary people, who are taking such insurance, can get the best treatment in any hospital. This is one of the schemes of the UPA Government. But it is not given to the people directly because the insurance agent who is selling this product will not get commission. Therefore, he is not propagating it. Therefore, Sir, I would request that it is high time that the hon. Minister should take into consideration all these things and make Finance Minister give more money. (Time bell) Finally, Sir, I want to make one point. As the parliamentary proceedings are broadcast, the executive activities are broadcast, a person can go and see the judicial proceedings, there should be a place for broadcasting the judicial verdicts in the Supreme Court or in the High Court. That day should come. Then only, there will be a ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Natchiappan, this subject of broadcasting the judicial proceedings will not come under the purview of the Information and Broadcasting Ministry.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: When the hon. Chairman is taking a very hard decision of broadcasting whatever happens inside Parliament, why should not the judiciary take the same responsibility and broadcast what happens inside the court?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is the Parliament, which is permitted.

SHRI E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, it is time to broadcast everything. Transparency should be there for the judiciary also and for everybody, Sir.

Finally, I request the hon. Minister to consider this. There is no need to have a Censor Board at all, Sir. Already in the television broadcasting, there is a lot of vulgarity. We cannot regulate it even by an Act. From Hong Kong, everything is broadcasted. Who is going to stop it from Hong Kong? Rich people, middle-class people, and youngsters watch adult channels. Can we stop it in Hong Kong by law? We cannot do it. Therefore, why do we need the Censor Board now? If there is vulgarity in a film, let the court decide it. Let there be a law for that, and let the court decide it, Sir.

With this observation, I request the hon. Minister to devote some more time to this Ministry, because he is having only one portfolio other than the Ministry of Parliamentary Affairs. After the Parliamentary work, I hope he will pay much more attention to the total revamp of the Ministry. Thank you, Sir.

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (बिहार) : धन्यवाद, उपसभापति महोदय। दरअसल मैं अभी बाहर से आ रहा हूं और विषय के लिए पूर्णत: तैयार नहीं था, लेकिन यहां आने के बाद मैंने हमारी फेमिली फ्रेंड और बहुत काबिल सांसद जया बच्चन जी को सुना और उन से प्रभावित हुआ। मैं ने सोचा कि पूरी तैयारी न होने के बावजूद मैं अपने कुछ विचार आप के सामने रखूं।

सर, हमारे मंत्री जी बहुत काबिल, एमंपिटेंट, क्वालीफाइड, और बहुत फेवरिट मंत्री हैं, अच्छे मंत्री हैं और यह मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप के माध्यम से कुछ बातें उन के सामने रख पा रहा हूं। दरअसल भारत सरकार में कई मंत्री आए-गए, मंत्रालय रहा, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल होता रहा, बदलाव आता रहा। उस हिसाब से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग मिनिस्ट्री की जो शाखाएं हैं - फिल्म्स, टेलिविजन, प्रिंट मीडिया, दूरदर्शन, फिल्म्स डिवीजन और आकाशवाणी - इन सारी चीजों में या तो बदलाव नहीं आया या बदलाव आया तो ऊपर की ओर नहीं गया बल्कि उतार की तरफ गया। अभी जैसे कि हमारे सांसद वल्गैरिटी की बात कह रहे थे। तो वह जो चर्चा बहुत जोर-शोर से शुरू हुई है, उस के पहले मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। पहले मंत्रालय को कार्य-प्रणाली के आधार पर तीन भागों में करें - दूरदर्शन यानी टेलिविजन इंडस्ट्री जिस का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ प्रचार-प्रसार होता है बल्कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट भी होता है।

महोदय, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं आप के माध्यम से संक्षेप में अपनी बातें रखूंगा ताकि बातें ज्यादा समझ में आएं, उन का फैलाव न हो। मैं समाधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस का समाधान आप लेकर आएं, आप इस बारे में प्रकाश डालें। महोदय, आज एंटरटेनमेंट के नाम पर जो भी टेलिविजन इंडस्ट्री में हो रहा है, क्या वह सही मायनों में एंटरटेनमेंट हो रहा है? एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन आज उस में बहुत फैलाव आ गया है, उस में बहुत मिलावट है, बहुत गिरावट है। आज हम हिंदुस्तान के लोग अगर बात करते हैं तो शायद 15 प्रतिशत लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, 85 प्रतिशत लोग पूरे भारतवर्ष में रहते हैं और यह भी आज दुर्भाग्य है कि 15 प्रतिशत लोगों ने पूरे 85 प्रतिशत लोगों पर कब्जा कर के रखा

हुआ है। चाहे एंटरटेनमेंट का मामला हो, कार्पोरेशन का मामला हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का मामला हो, ट्रेड व बिजनेस का मामला हो और मल्टी-नेशनल का मामला हो, हम पूरे हिंदुस्तान को उसी नजरिए से देखना चाह रहे हैं। तो जब उन्होंने वल्गैरिटी का जिक्र किया तो यहां आपस में बहस होती है कि इसे छोड़ दिया जाए, ऑडिएंस को एतराज नहीं है। अगर देवी-देवताओं के नंगे फोटो दिए जाते हैं, कोई बात नहीं। कौन माइंड करता है? यह तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आखिर कहां तक हमने यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जाने दिया है? हो सकता है कि हमें तकलीफ न हो, लेकिन हमारी बुआ जी को होगी, पिता जी को होगी, दादा जी को होगी, हमारी बहनों को होगी, भाइयों को होगी, परिवार वालों को होगी, गांव वालों को होगी, छोटे छोटे शहर वालों को होगी। ...(व्यवधान)...

PROF. P.J. KURIAN: Mr. Sinha, this point has been raised again and again. So, I am forced to ask you a question. You see a film on television. You only know the name of the film. We see the film with our family and obscene scenes come. Then, you say, audience should decide. How can we decide? Only when we see, we find that it is obscene. ...(*Interruptions*)... I am only asking a question. I don't know that is why I am asking.

SHRI SHATRUGHAN SINHA: I have not come to that point yet. I have not said that. I am saying something else.

PROF. P.J. KURIAN: Shrimati Jaya*ji* has said, "Switch off". But switch off can be only after seeing it. That is the problem.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: But, Sir, how would you know whether it is proper or not proper if you don't see it. You have to first see something and then you switch off. First you have to see and it registers in your mind, then, you switch off. You can't pre-empt it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Or go for CAS! ...(*Interruptions*)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, the debatable question is this. Whether something obscene should be permitted. Why should it be permitted? After seeing, we can switch off.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But, somebody has to see.

SHRI JANARDHANA POOJARY: No, no, somebody ...(*Interruptions*)... You chaired the Censor Board. (Interruptions) It is in the interest of the nation.

SHRI SHATRUGHAN SINHA: Sir, I tend to agree with him. Sir, my point was ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: We know that you will agree with good suggestions.

SHRI SHATRUGHAN SINHA: I know you are a good man. You will only come up with goods suggestion. ...*(Interruptions)*...

SHRI HARISH RAWAT (Uttaranchal) : You are the only good man in BJP. (Interruptions)

SHRI SHATRUGHAN SINHA: Thank you very much. I hope my other colleagues do not take it seriously. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद : भावी मुख्य मंत्री ने कहा है, तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHATRUGHAN SINHA: Sir, as I was saying, 85 per cent of people are living in Bharat, अभी क्या होता है कि 15 प्रतिशत या 20 प्रतिशत लोग जो बड़े शहरों में हैं, वे पूरे देश का ठेका ले लेते हैं कि जो इंडिया में हैं, और वे समझते हैं कि जो देख रहे हैं, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वह पूरे देश के लिए, देश के लोगों के लिए सही है। शायद ऐसा नहीं है। जैसा अभी हमने कहा थोड़ी देर पहले, कि कोई वल्गैरिटी की बात हुई, कोई ऑफ-सीइंग सीन की बात हुई या कोई देवी देवता को जिस तरह से गलत तरीके से पेंट किया, मैं कहीं पर जाता हूं और बहस होती है, तो कहते हैं कि so what? After all, nobody minds. It is the freedom of expression. But the freedom of expression also has some limitations. You can't go up to that extend, कि जो करके दिखा दे, You have also to think that our people are also living in other parts of the country. बुआ, मामा, चाचा, ताऊ, पापा, दादा, बेटा, बेटी, भाई, बहन, गांव वाले, छोटे शहर वाले, they feel very hurt. और यही कहने से काम नहीं चलेगा कि टेलीविजन में सबेरे पत्नी कोई और है और रात में पत्नी कोई और होगी। जब टेलीविजन एंटरटेनमेंट के नाम पर खोलने जा रहे हैं, तो पता ही नहीं कि कौन किसका पति किसके साथ भाग गया, वहां पर किस की पत्नी किसके साथ जुड़ गई। We do not know. और यह कहना कि नहीं, एंटरटेनमेंट है, Certainly, it is not healthy entertainment. But I will not take much time on this particular issue. I think the message is conveyed, जो मैं यह कहने जा रहा था कि एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ मोरबिडिटी और वल्गैरिटी भी आ गई है।

सर, इंफोरमेशन के नाम पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड आज हमारे टेलीविजन की क्रेडिबिलिटी सबसे कम है और यह बहुत सी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। हमारे दूरदर्शन की मैं ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करता, मगर बहुत लोगों की नजरों में यह झूठ-दर्शन भी नाम रखा है। रीच तो बहुत ज्यादा है, मगर क्रेडिबिलिटी कहां है? क्रेडिबिलिटी यह है कि अभी भी लोग कहते हैं कि सीएनएन क्या कह रहा है और बीबीसी क्या कह रहा है। तो क्रेडिबिलिटी के मामले में हम कुछ नहीं कर पाए हैं, इतनी सरकारें बदलीं, इतने मंत्री बदले। आप हमारे बहुत काबिल मंत्री हैं प्रियरंजन दास मुंशी जी, जो यहां बैठे हैं और हमारे पीछे हमारे छोटे भाई रवि

5.00 P.M.

शंकर प्रसाद जी भी बहुत अच्छे मंत्री रहे हैं, जिन्होंने इस मंत्रालय में अच्छे अच्छे काम किए थे। फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूना में जो एक्टिंग कोर्स नहीं होता था, उसे 22 साल के बाद फिर से इन्होंने अपने जमाने में शुरू कराया। अभी यह बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन चला शुरू होना भी एक बहुत बड़ी बात है, और अगर आप चाहेंगे, तो बहुत अच्छे ढंग से उसका समाधान हो जाएगा। मैं सिर्फ कुछ बातें सामने रखना चाहता हूं। डाकूमेंट्री फिल्म डिवीज़न sometimes, is known as the sure cure for insomnia. आज उसका रेपुटेशन यह हो चुका है कि किसी को अगर तीन महीने से नींद नहीं आ रही हो, उसको डाकूमेंट्री दिखा दें, वह केवल एक डाकूमेंट्री देखकर फौरन सो जाएगा। यह क्रेडिब्लिटी हमारी डाकूमेंट्री की है।

प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छा है, रीडर एस्पाइरेशंस है, बहुत अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, खुलकर बातें होती हैं। लेकिन, कई बार गलत बातें हो जाती हैं, आपके तथा हमारे चरित्र पर अटैक होता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिनके हम हकदार नहीं हैं। बहुत सारी बातें अभी श्रीमती जया बच्चन पर भी हो रही हैं, जिनमें बहुत सच नहीं हैं और बहुत सारी बातों को जान-बूझकर किया गया है। यह सिर्फ श्रीमती जया बच्चन की ही बात नहीं है, हम सब कभी न कभी इसके शिकार होते ही हैं।

स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने आए। जब सामने वाले पर हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब अपने ऊपर हो रहा है तो हम रो रहे हैं! कांग्रेस पर हो रहा है तो हम खुश हो रहे हैं, बीजेपी पर हो रहा है तो हम रो रहे हैं, यानी वाइस-वर्सा। यह स्टिंग ऑपरेशन जहां तक सच्चाई उजागर करते हैं, जहां तक ढंग से इन्फारमेशन देते हैं, वहां तक तो सही है, लेकिन जहां पर ये ऑपरेशंस चरित्र हनन कर रहे हैं, जहां पर ये अपना मकसद सीधा कर रहे हैं, वहां ये गलत हैं। स्टिंग ऑपरेशंस के बारे में मैं बता दूं कि स्टिंग ऑपरेशन से कोई समाज की सेवा नहीं हो रही है, ज्यादातर स्टिंग ऑपरेशंस का एक दाम होता है, एक प्राइस लिया जाता है कि फलां चैनल को दिया जाता है, फलां चैनल को पैसे दिए जाते हैं तथा यह एक व्यापार है और इस व्यापार के शिकार हम हो रहे हैं, आप हो रहे हैं, हमारा पूरा परिवार हो रहा है। उस पर आखिर अंकुश लगाने के लिए, चैक एंड बैलेंस के लिए अभी तक क्या किया गया है? क्या कर सकते हैं? प्रिंट मीडिया जो कर रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया गया है या हम क्या कर सकते हैं? डैमेज किया फ्रंट पेज पर और जोर पड़ा तो बड़ी मुश्किल से क्लेरिफिकेशन हुआ 11वें पेज के 9वें कॉलम में, इतना छोटा! क्यों? कब तक? इसके लिए मंत्रालय क्या कर रहा है? मैं सारी बातों को संक्षेप में रख रहा हूं तथा मैं चाहूंगा कि इस पर पूरे पार्लियामेंट की, पूरी संसद की सहमति हो और मुझे लगता है कि वह सहमति होगी, क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। हमाम में हम सबको तकलीफ हो रही है।

मैंने थोड़ी देर पहले फिल्म इंस्टिट्यूट आफ इंडिया का ज़िक्र किया था, The Film Institute of India is the most prestigious institutes of its kind, perhaps, one of the most prestigious institutes in the whole world. जब शुरु हुआ। अगर रेट आफ सक्सैस देखें फिल्म इंस्टिट्यूट आफ इंडिया की, The kind of people who have come out from this Institute shows that not only the Film Institute of India is

one of the most prestigious institutes in India, especially, in Asia, but also one of the most successful institutes in the whole world. आप जितने नाम ले लें, श्रीमती जया बच्चन तो यहां सामने बैठी हुई हैं - शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, डैनी डेंग्जोंपा, मिथुन चक्रवर्ती, असरानी, पेंटल, शत्रुघ्न सिन्हा...(**व्यवधान**)... ये सारे लोग और टैक्निशियंस में श्री संजय लीला भंसाली, के0के0 महाजन, विदु विनोद चोपड़ा और ऐसे अनेक लोग हैं। लेकिन आज वह इंस्टिट्यूट कहां है? आप लोगों ने कोशिश की, रवि शंकर जी हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की और आप भी आई एम श्योर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको समझना जरूरी है कि आखिर वे दिन कहां गए, वे बातें कहां गईं। जिस फिल्म इंस्टिट्यूट का एक नाम होता था, एक शान होती थी, वह एक चीज होती थी, आज उस फिल्म इंस्टिटयूट में इतनी गड़बड़ी क्यों है?

श्रीमती जया बच्चन : फेकल्टी नहीं है।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : फेकल्टी नहीं है और जो ऐडवाइज़री कमिटी है, उसमें कौन लोग ऐडवाइज़र रखे गए हैं? ऐसे लोग हैं, जिनका फिल्म इंस्टिटयूट से दूर-दूर तक कोई रिश्ता-नाता नहीं है। ऐडवाइज़री कमिटी में न नसीरुद्दीन शाह हैं, न श्रीमती जया बच्चन हैं, न शत्रुघ्न सिन्हा हैं, न डैनी डेंग्जोंपा हैं, न मिथुन चक्रवर्ती हैं। ऐसे लोग, जिन्होंने उस इंस्टिट्यूट को एक नाम दिया, कांट्रिब्यूट किया, उनके नाम कहीं नहीं हैं। आज वे लोग कहीं नहीं हैं, बल्कि कोई मुंगी लाल, कोई चंपक भाई लाए जा रहे हैं।

श्रीमती जया बच्चन : मेन ऐडवाइज़री बॉडी में इन लोगों में से कोई नहीं है, मगर जो दूसरी एक बॉडी है उसमें नसीरुद्दीन भी हैं, शबाना भी हैं और डैनी भी हैं।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : मैं मेन एडवाइज़री कमेटी की बात कर रहा था। मैं यह कह रहा हूं कि हमें इस बात को और समझने की जरूरत है कि कैसे इसे और अधिक चुस्त और दुरुस्त किया जाए। मैंने टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात की, डॉक्युमेंटरी की बात की, प्रिंट मीडिया की बात की, फिल्म इंस्टीट्यूट की बात की, चम्पक भाई और मुंगी लाल जी की भी बात की, इन तमाम बातों के बाद मंत्री महोदय मैं आपके माध्यम से केवल एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे मित्र राजीव शुक्ल जी भी आ गए हैं ...(**व्यवधान**)... सर, मैं केवल एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी हमारी फैमिली फ्रैंड श्रीमती जया बच्चन जी ने भी कहा, मैं उनकी उस बात से कुछ हद तक सहमत जरूर हूं, लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, जहां सैंसरशिप का मामला है, मेरा खयाल है कि मैंने जो कहा कि 85 per cent of the people living in Bharat and 15 per cent people living in India, यह सच है। सैंसरशिप की जरूरत है और ढंग से जरूरत है, क्योंकि हमारी हिन्दी फिल्म with due respect कुछ लोगों को छोड़ कर और बहुत काबिल लोगों को छोड़ कर, ब्लैक एंड वाइट से शुरू हुई, कलर्ड फिल्म की ओर आई और अब कलर से उनका झुकाव ब्ल्यू फिल्मों की ओर भी आ चुका है। अगर उन्हें रोका और टोका न गया तो जैसा अभी हमारे सीनियर कुलीग श्री पुजारी साहब कह रहे थे कि यह ऑब्सेनिटी वहां तक बढ़ेगी, जहां तक आज बढ़ गई है। आज हमें दिक्कत आती है कि मां-बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ उसे देखें या न देखें अथवा देखें तो क्या देखें। इसलिए आज इसे रोके-टोके जाने की जरूरत है, सैंसरशिप को और अधिक चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने स्कर्ट पहनी हो तो उसे काट दें और

फिल्मों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमी दिखाई पड़े। हम इसका मतलब यह माने कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या कपड़ों की कमी है और उस फिल्म को रोक दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होना यह चाहिए कि आपकी विचारधारा से लेकर आपके हाव-भाव, आचरण, व्यवहार, इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए। भले ही आप उसके लिए एक टीम बनाएं, आप ऐसे लोगों को लेकर आएं जो कि चारों तरफ की सोसाइटी के भिन्न भिन्न ...**(समय की घंटी)**... सर, आप दो मिनट ठहरिए, मैं आपनी बात एक घंटे में खत्म कर दूंगा ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: यह बहुत दिन के बाद बोल रहे हैं।

श्री उपसभापति: लगता है श्री परमार साहब को अपना नाम वापस लेना पड़ेगा।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: नहीं सर, मैंने तो आपसे कहा ही है कि आप पांच मिनट ठहरिए, मैं एक घंटे में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

सर, इसमें समाज के भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों को शामिल करें। यह जरूरी नहीं है कि वह कोई ब्यूरोक्रैट हो या इंटलेक्चुअल हो या फिल्म इंडस्ट्री से हो, जो भी हो लेकिन सैंसरशिप जरूर होनी चाहिए। अगर आप इसे हमारे हाथों में छोड़ देंगे और फिल्मों के लोगों पर छोड़ देंगे, आप छोड़ कर देख भी चुके हैं, इससे तो बात कहां से कहां तक बढ़ गई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अगर वह किसी खास विचारधारा की हो, किसी के फेवर में या एगेंस्ट में हो अथवा वह एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन या पर्टिकुलर इंडीवीडुअल को सूट नहीं करती है और इसलिए उस फिल्म को नहीं दिखाया जाए, उसे रोक दिया जाए, यह गलत है। लेकिन टोटैलिटी में हाव-भाव, आचरण, व्यवहार, भाषा पहनावा, कल्चर, संस्कृति, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सैंसरशिप बहुत जरूरी है।

अन्त में एक आखरी बात पर थोड़ी रौशनी डालते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सर, जया बच्चन जी ने वीडियो पाइरेसी के बारे में कहा, मैंने तेरहवीं बात जया बच्चन जी का नाम लिया है, चूंकि आज तेरह तारीख है। इस बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्य प्रणाली से एक अपेक्षा तो अवश्य है कि यह वीडियो पाइरेसी खत्म होनी चाहिए। किसी को भी किसी के इंटलेक्चुअल राइट्स को, किसी के कॉमर्स को, किसी के बिज़नेस को छीनने का हक नहीं है, यह झोंपड़-पट्टी में दिखाई जा रही है या बसों में दिखाई जा रही है, कि होटलों में दिखाई जा रही है, यह ठीक नहीं है। फिल्म अभी रिलीज हुई या नहीं हुई, उसके पहले किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में या बाकी जगह रिलीज़ हो गई या फिर रिलीज़ होने के साथ-साथ ही रिलीज़ हो गई। इससे प्रोड्यूसर्स का और फिल्मों से जुड़े हुए लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है, हो क्या जाता है हो रहा है और होता रहेगा। कुछ जगह ऐसा जरूर है कि जहां कुछ ऐसे मज़बूत या दमदार लोग हैं, जो अपने कामों से शायद वीडियो पाइरेसी रोक लेते हैं, लेकिन यह हर जगह संभव नहीं है और इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, लेकिन ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जया बच्चन: साउथ में हुआ है।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा: हां, साउथ में भी हुआ है और महाराष्ट्र में भी कुछ खास लोगों की वजह से कुछ खास फिल्मों को रोका गया है, वीडियो पाइरेसी तो नहीं हुई है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है और न ही हो सकता है। इसमें सरकार को ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, मंत्री जी भी सामने बैठे हुए हैं, साथ-साथ सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और

मंत्री जी से खास अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे कि कोई जब हमारी फिल्मों को दिखाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, उन्हें भी शायद बड़ी तकलीफें होती होंगी, जिनकी धुनें हम फिल्म वाले चुराते हैं, कहानी चुराते हैं। अगर उनकी कंट्री के साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है और हम आउट राइट चोरी करके उनके सब्जेक्ट्स पर यहां फिल्में बनाते हैं, What is right for Peter should be right for Paul. अगर हमें दर्द होता है कि हमारी कोई पाइरेसी करता है तो उन्हें भी दर्द होता होगा जिनकी कहानियां चोरी करते हैं हम -"मोरे पिया घर आया हो लाल जी।" को सीधे कर देते हैं -मोरे पिया घर आया हो राम जी। सीधे नुसरत फतह अली के लिए एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। अभी हाल ही में ताज्जुब हुआ, हमारे मित्र बप्पी लहिरी जी ने, दादा जी के तो बहुत ज्यादा खास मित्र हैं, बप्पी लहिरी जी ने अमेरिका में केस किया कि उनकी धुन किसी ने चुराई है, उस पर केस करके आउट ऑफ दी कोर्ट सेटलमेंट करके पैसा लिया और जिंदगी भर उन्होंने शायद कितनों की धुनें चुराई हैं, उनको ढूंढ रहे हैं लोग, उनको कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है कि piracy is wrong. In the same way, even that is wrong. We, the stage people, thought that सीन बाई सीन चोरी करते हैं; विद ड्यू रेसपेक्ट, गुलजार साहब बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं। मगर गुलजार साहब का उदाहरण दे रहा हूं । I have nothing against Gulzar Sahib.

श्री उपसभापति : नाम मत बोलिए।

SHRI SHATRUGHAN SINHA: I am not criticising him, Sir. I have also worked in his films. He is a very good director. He is a very good man. फिर चाहे "कोशिश" ले लें आप, जिसमें जया बच्चन जी भी थीं। या "मेरे अपने में" जो तपनदा की थी, अपुनजान खैर परमिशन से ली गई थी, परमिशन के साथ बनाई गई थी। या उनकी वह फिल्म जो साउंड और म्यूजिक पर बनी थी -"परिचय" ऐसी ये सब पुरानी बातें हैं। अभी भी इतने लोग...*(व्यवधान)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: The film "Parichay" is not taken from "Sound of Music". It is taken from a Bengali story.

SHRI SHATRUGHAN SINHA: I stand corrected. But your "Koshish" was taken from ...*(Interruptions)*... That is a different thing. हम यह कहना चाह रहे हैं कि इसका भी कोई मेकेनिज्म होना चाहिए कि अगर हमारी पाइरेसी के लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पाइरेसी न हो, इसको रोकना चाहिए, जरूर रोकना चाहिए। साथ ही साथ सूचना मंत्रालय को इस पर भी कोई रोशनी डालनी चाहिए कि हम जो लोगों की चोरी कर रहे हैं, दिन दहाड़े जो डाके मार रहे हैं, उनकी फिल्म चोरी कर रहे हैं, उनके आइडिया चोरी कर रहे हैं, उनके सीन चोरी कर रहे हैं, उनकी धुनें चोरी कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए और सिर्फ हम फिल्म वालों को या टेलीविजन वालों को इसका अधिकार नहीं मिलता यह कह कर बचने का कि हमारी ट्रीटी हुई है इस कंट्री के साथ, तो पाकिस्तान की हम चोरी कर लें, पाकिस्तान हमारी फिल्में चोरी कर ले। पाकिस्तान की एक फिल्म थी, मैंने भी वहां की दो फिल्मों में काम किया है। वहां की फिल्म थी -"नौकर वहुरी दा", हिन्दुस्तान में फिल्म बनी - "नौकर बीवी का", और सेम सब्जेक्ट। वहां पर एक फिल्म थी -"मौलाजग", उसकी हिन्दी

फिल्म थी -"जीने नहीं दूंगा", जिसमें धर्मेन्द्र और मैं था। बाद में पता चला कि वह चोरी की गई है, लेकिन उस वक्त पता नहीं था। सर, ईमानदारी से बोल देता हूं। मैं समझता हूं कि इस पर भी गौर करना चाहिए।

मंत्री जी, पचौरी साहब भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन हमारी आखिरी बात को रोकने की कोशिश मत करिए।

श्री हरीश रावत : इस प्रकार बहुत सारी चीजें हम चोरी की देखते रहे और चोरी की सुनते रहे। आज मालूम पड़ा है यह सब।

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : लेकिन यहां तो कई बार चोरी और सीना जोरी भी होती है,सर। Thank you, Mr. Minister. Thank you very much, Sir, for having given me this opportunity. I hope he will take care of these things.

SHRI V. NARAYANASAMY: You spoke after a long time.

SHRI SHATRUGHAN SINHA: You don't allow anybody to speak, Sir. Thank you very much, Sir.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM : Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you very much for permitting me to air my views on the working of the I & B Ministry. Different views have been aired on the working of the Information and Broadcasting Ministry.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I will be very brief. I am not known to make a long speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I know that.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, the Doordarshan, as was pointed out by many of my friends, has got far and wide reach in this country. It has the low power transmitters all over the country and, therefore, the reach is more. But, what is unfortunate is that the quality of telecast by the Doordarshan is not up to the level of the private telecasters. I would request the hon. Minister to go digital, as far as Doordarshan is concerned. A lot of time is wasted. Sometimes, when a change-over of Kendras takes place, we have seen that the television is going blank. Sometimes, the National Kendra is changed to the Regional Kendra or the Regional Kendra is changed to the National Kendra. Some letters appear and nothing happens. On the contrary, when we see some of the very popular television channels, like the Sun TV, every ten seconds they show some advertisements and make money out of it. Such things should be

encouraged and it should be commercialised. At least, some sort of entertainment must go on, instead of going just blank.

Sir, there is also no proper management of the Doordarshan. It is not managed professionally. The DD News Channel, which was started with a lot of hope, has become a boring channel altogether when compared with other channels. At least, presentation of news by the DD News Channel should be comparable with other news channels, if not entertainment. I would request the hon. Minister to advise the Doordarshan to start an exclusive music channel fully devoted to Indian classical light music in all languages. Further, there should be an exclusive channel for information on travel and tourism. Travel and tourism is one particular area which attracts a lot of viewership. So, there should be an exclusive DD Travel channel.

Sir, some Doordarshan Kendras have been started recently. I would like to talk about one Kendra which was started in Madurai. It was started with a huge investment. Shri Natchiappan also spoke about the Madurai Studio. Though it was started recently, it has not contributed much. We expect a lot of contribution from the Madurai Kendra. The Madurai Kendra does not cover local news and cultural events in Tamil. My request is some coverage must be given to the local Saurashtra language which is spoken by a group of people in Madurai. In this way, this particular group should be given some encouragement. Thank you.

श्री उपसभापति : श्री तरलोचन सिंह। सिर्फ पांच-पांच मिनट बोलना है।

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा) : सर, मुझे यह कहने में खुशी है कि आज हम इन्फारमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की वर्किंग को डिसकस कर रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस किसी और मिनिस्ट्री से कम नहीं है। इंडिया की डेवलेपमेंट के लिए जितना रोल यह मिनिस्ट्री अदा कर सकती है, शायद ही और कोई करती हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह मिनिस्ट्री केवल रेडियो और टी0वी0 पर ही निर्भर है और कुछ नहीं है। मुझे याद है कि इस मिनिस्ट्री के ऐसे-ऐसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट थे, जिनकी पॉपुलरिटी सारे देश में थी। फिल्म डिवीजन की न्यूजरील बहुत ही पॉपुलर थी और हर सिनेमा घर में दिखाई जाती थी, उसे दिखाना कम्पलसरी था। फील्ड पब्लिसिटी यूनिट गांव-गांव में घूमती थी और उनके पास फिल्म होती थी और सारे गांव के लोग इकट्ठा होते थे। कम्युनिटी लिसिनिंग स्कीम रेडियो की थी, हर पंचायत में उसकी पॉपुलैरिटी थी। एक्जीबिशन विंग इसका बहुत इम्पोर्टेंट था और किसी वक्त ड्रामा और लाइट एंड साउंड शो, मुझे याद है आज से कोई 30 साल पहले कर्मल गुप्ता ने एक शो अमृतसर में तैयार किया, जब गुरू नानक देव जी का 500वां सालाना मनाया गया, आपकी मिनिस्ट्री का वह शो एक साल चला और सारे पंजाब के करीब एक करोड़ लोगों ने उसको देखा और हर रोज लोग आपको धन्यवाद करते थे कि यह क्या मंत्रालय है जिसने इतना बड़ा शो किया है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मिनिस्टरी के ये सारे हिस्से खत्म हो गए। सर, आज

दूरदर्शन की बात चल रही है। इसमें एक बात देखने में आती है कि टेक्निकल फॉल्ट बहुत अधिक होता है। बहुत बार चलते-चलते जितने ये रुकते है, टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर, यह समझ में नहीं आता कि सबसे पुराना चैनल हो, सबसे अच्छे इंजीनियर्स हों और सबसे बड़ा इक्विपमेंट हो, फिर ऐसी क्या बात है कि टेक्निकल फॉल्ट मैक्सिमम इस चैनल पर आता है? कई बार तो जो एंकर अनाउंस करता है कि यह फिल्म देखो, तब जोड़ने वाले नीचे रह जाते हैं और वे खाली बैठे रहते हैं। इसके ऊपर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राइवेट चैनल्स में बहुत अधिक कम्पीटिशन है। कम्पीटिशन करते-करते वे भूल जाते हैं कि क्या वे देश का कुछ भला भी कर रहे हैं या सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए उसे चलाते हैं? उपसभापति महोदय, मैंने सुबह आपसे भी अर्ज किया था कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्राइवेट चैनल्स के लिए आज तक नहीं बना। बात यह है कि हम बहुत अधिक डरते हैं। आज प्रेस हमारे ऊपर इतनी अधिक हावी हो चुकी है कि किसी को भी इनसे कोई अच्छी बात करने में भी डर लगता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े और पुराने चैनल ने एक ऐसा "देशद्रोह" प्रोग्राम दिखाया, जिससे इतने लोग दुखी हुए कि आखिर चैनल को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि अगर ये कोई ऐसा गलत प्रोग्राम दिखाते हैं तो इनका क्या हाल किया जाए। प्रेस काउंसिल प्रेस के लिए है, लेकिन चैनल्स के लिए अभी तक कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो इनका कुछ कर सके। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक कमर्शियलाइज़ेशन है। मैं एक-दो मिसालें देना चाहता हूं। एक चैनल है - "ईटीसी पंजाबी" - सुबह पांच घंटे, चार से लेकर नौ बजे तक विदाउट ईवन वन सेकेंड कमर्शियल ब्रेक, वह गोल्डन टेम्पल का कीर्तन रिले सारे वर्ल्ड में करता है। करीब तीन-चार करोड़ लोग उसको देखते हैं और एक आने का भी कमर्शियल बेनेफिट उसको नहीं है। वह कैसे चलता है? हम बाकी प्राइवेट चैनल्स का कुछ नहीं करते। ऐसे ही आजकल बहुत अच्छा प्रोग्राम योग पर आ रहा है - इंडिया टीवी पर, आधे घंटे का प्रोग्राम आता है और सारी दुनिया खुश है, वह दोपहर को और सुबह आता है। इस तरह से प्राइवेट चैनल्स इतने अरबों-करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उनको क्या हम ऐसी कोई बात कह सकते हैं कि वे भी कुछ ऐसे प्रोग्राम दिखाएं, जिससे लोगों का भला हो, लोगों को देश की संस्कृति का पता चले? मुझे याद है, श्री मिश्रा Patriot के एडिटर थे, उन्होंने भारत के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दूरदर्शन पर दिखाया था। वह इतना अधिक पापुलर था कि इंडिया की पिछले तीन-चार हजार साल की हिस्टरी उस सीरियल में दिखायी थी। इस प्रकार ऐसे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम अगर दूरदर्शन वाले दिखाएं तो इसका हम सबको बहुत लाभ होगा क्योंकि प्राइवेट चैनल वाले इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। रेडियो की पापुलैरिटी बहुत अधिक है और रेडियो की इम्प्रूवमेंट भी बहुत है। जो आपके दूसरे फॉरेन चैनल्स हैं, इनको लोग बहुत देखते हैं। इस पर जितना भी आप खर्च करो और जितने भी पैसे लगाओगे, उससे देश का भला होगा। एक बात मैं, मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दूरदर्शन और रेडियो, रिजनल लेंग्अुएज की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं कि जो नॉर्थ रीजन है, यह सारा पंजाबी स्पीकिंग रिजन है, चाहे स्टेट्स अलहिदा हैं - चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो या कश्मीर हो। उसके साथ-साथ पाकिस्तान में आठ करोड़ पंजाबी रहते हैं जो सब पंजाबी बोलते हैं। लेकिन दूरदर्शन को इतना कुछ कहने के बावजूद भी पंजाबी न्यूज़ का चैनल नहीं है - कश्मीर में नहीं है, सिर्फ पंजाब तक सीमित है। हरियाणा में पंजाबी सेकेंड लेंग्अुएज है, दिल्ली में पंजाबी सेकेंड लेंग्अुएज है, लेकिन दूरदर्शन और रेडियो पंजाबी लेंग्अुएज को न न्यूज़ में और न ही प्रोग्राम में दिखाने को तैयार हैं। इससे

आपको एडवांटेज होगा। सारा पाकिस्तान, जिसके साथ आज हम दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वह पंजाबी स्पीकिंग है - आप अपने प्रोग्राम उधर फोकस क्यों नहीं करते? पंजाबी में अगर आप अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे तो दूसरे देश से दोस्ताना संबंध बनाने में हिन्दुस्तान को बहुत लाभ मिलेगा। अभी जया बच्चन जी ने सेंसर की बात की। मंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड कायम है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि कई रिलीजियस ईश्यूज़ पर फिल्में चलाई जाती हैं। बहुत से रिलीजियन के लोग, खास करके माइनॉरिटीज़ के लोग, जब कोई ऐसी फिल्म आती है जिसमें रिलीजियस फीलिंग हर्ट होती है, उससे दुखी होते हैं। पीछे दिल्ली में इतना बड़ा एक फिल्म के ऊपर हुआ, मुम्बई में भी हुआ। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जितनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनका एक-एक आदमी, ऐज़ एडवाइज़र, जिस फिल्म में किसी रिलीजियन की कोई बात हो, उनको एक बार पहले दिखा लिया करें। उससे क्या होगा कि कोई झगड़ा नहीं होगा, फिल्मों की वजह से कोई लड़ाई नहीं होगी। तो जितने सेंसर बोर्ड हैं, उनमें कम से कम, जैसे मुम्बई में हैडक्वार्टर है, मुम्बई में हर माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका कोई न कोई ऐडवाइज़र उसमें रखवा लिया करें, ताकि ये झगड़े बाद में न हों। ऐसे ही कई मैगज़ीन्स में, अखबारों में कई रिलीजन्स के jokes आते हैं। उसके लिए उनको लिखा जाता है, तो वे बाद में एक लाइन में माफी मांग लेते हैं। तो ऐसा भी किया जाए, क्योंकि देश में हम एकता चाहते हैं और छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई होती है।

महोदय, एक बात मैं और आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि नेशनल इंटिग्रेशन की देश को बहुत जरूरत है, उसके लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को स्पेशल प्रोग्राम करने चाहिए। हिंदुस्तान में हमारे बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान हैं, जहां सारे लोग जाते हैं, सब कौमों के लोग जाते हैं। उन स्थानों के प्रोग्रामों को ज्यादा हाइलाइट करना चाहिए, ताकि यह पता चले कि हम सब देश में किस तरह इकट्ठे रहते हैं ! Advertisement पॉलिसी में आम शिकायत यह है कि हम इसको पोलिटिसाइज करते हैं। जितने ad आप देते हो, ये तमाम अखबारों को मिलें, खास तौर पर जो रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं, जो लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स हैं, वे हिंदुस्तान में बहुत बढ़ गए हैं, उनकी गिनती ज्यादा है, लेकिन जब ad देते हैं, तो they are always english-oriented. इसलिए लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को, खासकर रीजनल लैंग्वेजेज़ को, मैं पंजाबी की फिर बात करता हूं, उनको बहुत कम हिस्सा मिलता है, मैगज़ीनों को तो मिलता ही नहीं है, एकाध अखबार को मिलता है, तो इस ओर भी खास ध्यान दिया जाए।

उपसभापति महोदय, एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि NRIs को आप हाइलाइट कर रहे हो, उनको award देते हो, उनकी सिटिज़नशिप का काम भी किया है। तो इस वक्त करोड़ों NRIs बाहर बैठे हैं, हमारा दूरदर्शन चैनल, ऑल इंडिया रेडियो, उनके जहां वे लोग रहते हैं, जितना काम करते हैं, उनके लिए स्पेशल फीचर फिल्म, स्पेशल डॉक्युमेंटरी तैयार करें, क्योंकि इस वक्त आपका चैनल सारी दुनिया में जाता है। हमारे वे ambassador जो बाहर बैठे हैं, वे कितना काम कर रहे हैं, तो उनको हाइलाइट करें और उनके बारे में स्पेशल फिल्म बनाकर हम दिखाएं।

अंत में मैं यह बात फिर कहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब sports से बहुत कनेक्टेड हैं और इनको यह बहुत बड़ी देन है। Sports एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। हर जगह लोग जाते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि हर जगह का रिले करते हो, लेकिन बाकी चैनल्स में भी आप वैसी पॉलिसी बनाएं कि sports का जो

सब्जेक्ट है, यह हाइलाइट हो। देश को इसका बहुत लाभ मिलेगा, देश की एकता को इसका लाभ मिलेगा और हमारे यूथ को जो बाहर जाते हैं, उनको वापस लेने का लाभ मिलेगा। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मंत्री बनते ही बहुत अच्छे काम किए। हमारी उम्मीद है कि इस मिनिस्ट्री को ज्यादा बजट मिले और ज्यादा काम करे, ताकि यह मिनिस्ट्री देश का ज्यादा भला कर सके, धन्यवाद।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यकरण पर आज चर्चा हो रही है। यह बात सही है कि भारतीय संस्कृति को कायम रखने के लिए, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे टी.वी. चैनल हो, लोगों की आशा तो यह थी कि भारतीय संस्कृति को बनाए रखेंगे, लेकिन आज जैसे टी.वी. चैनलों को देखते हैं, तो उससे हमारी संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचता है। प्राइवेट चैनल वाले तो पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, किसी तरीके से पैसा कमाया जाए, चाहे टैक्स चोरी किया जाए - टैक्स की चोरी भी हो रही है - इस देश में चैनलों के लिए दो तरह की फैसिलिटीज हैं - जो इंडियन चैनल हैं, प्राइवेट निजी चैनल, वे तो टैक्स देते हैं और जो बाहर के चैनल हैं, वे टैक्स नहीं देते हैं। जबकि कई ऐपिसोड, कई प्रोग्राम इंडिया में बनते हैं, इंडिया के कलाकार उनको बनाते हैं, वे एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, दूसरी जगह से हांग-कांग के नाम से चैनलों को प्रसारित किया जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो टैक्स-चोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, आप टैक्स कैसे लगाएंगे, जो दूसरे तरीके से चोरी की जा रही है टैक्स की, उसको कैसे रोकेंगे? मंत्री जी, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ तो टैक्स की चोरी हो रही है, वे लोग जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वे तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस देश के चैनल हैं, प्राइवेट चैनल वाले - दूरदर्शन तो पार्लियामेंट की हकीकत है, पार्लियामेंट में जो होता है, उसको दिखाते रहते हैं। लेकिन प्राइवेट चैनल्स इसको नहीं दिखाते हैं, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि प्राइवेट चैनल्स को भी मजबूर करें कि वे पार्लियामेंट की कार्यवाही दिखाएं। महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोड एंड कंडक्ट की बात भी कर रहे थे, यह लागू होना चाहिए। इतने गलत एपिसोड दिखाए जाते हैं, इतनी गलत चीजें दिखाते हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते? सर, रात दस बजे के बाद बच्चे TV देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्राइवेट चैनल्स ऐसे हैं, यदि बच्चों को वे चैनल्स दिखाएं तो वे गलत सोहबत में पड़ जाएंगे और वे गलत रास्ते पर चले जाएंगे।...**(व्यवधान)**... आप दस बजे के बाद के TV चैनल्स को देखिए, छोटे-छोटे बच्चों को...**(व्यवधान)**... गलत प्रचार-प्रसार न हो इसके लिए सैंसर बोर्ड है, लेकिन समझ में नहीं आता कि सैंसर बोर्ड से भी कैसे गलत फिल्में निकल जाती हैं? आप एडवर्डटाइजमेंट को देखिए, शर्म आती है, मां और बच्चे, भाई और बहन एक साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। इसलिए मंत्री जी, आप भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखें, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे। आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से दूरदर्शन को कंट्रोल करें, ताकि इसके माध्यम से लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, भले ही आप फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से या TV चैनल्स के माध्यम से, लोगों को अच्छे प्रोग्राम्स मिलें, लेकिन उनसे लोगों में सामाजिक ज्ञान पैदा हो तथा उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। इस प्रकार के प्रोग्रामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री मनोज भट्टाचार्य। आप पांच मिनट बोलिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री मूल चन्द मीणा : सर, बीजेपी की सीटें खाली हैं। ...**(व्यवधान)**...

डा0 फागुनी राम (बिहार): सर, बीजेपी की सीटें खाली हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : भट्टाचार्य जी, आप बोलिए।

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I will make a very limited intervention. I personally feel that there is no use of expressing repentance on the cultural degradation that is taking place in this country over a period of time; because, to my mind, Sir, culture is integrated with the economic policies that are pursued by the country. Now we have resorted to the economic policy, what we term as the neo-liberal economic policy where cultural integration is taking place all over the world and the Western culture is being dumped upon us. This is quite natural. Unless you are prepared to fight against that economic policies, you cannot isolately fight against the cultural decadence. I fully agree with the hon. Members who have mentioned about the cultural decadence that is taking place very vigorously in this country of ours. But, I am sorry to say that it cannot be isolately taken up for correction. The correction has to be made right from the economic policy itself. However, it is a subject where I can dwell for hours, but the time is not in my favour and I am not going to dwell for long.

I have assured that I will be making some very specific remarks or intervention particularly in regard to the All India Radio; because, Sir, the majority of our people in this country, even today, though television sets have been sold in numbers and the Government has also ensured that prices of television sets go down by adjusting the taxes, excise duty, etc, still then, a majority of the people in the rural India, particularly, who live in Bharat, who do not live in India, mostly hear the radio, All India Radio. It has been pointed out by various sources that Prasar Bharati--hon. Minister may kindly take a note of it--is planning to shift the regional languages like Bengali, Assamese, etc., etc.,--I do not quote all the languages over here--out of the headquarters of the national capital to the respective headquarters. The situation is such that the infrastructure in the State capitals is not there to accommodate these languages, the way they are done from the national headquarters. That infrastructure does not exist. The regional languages news services division has a long and rich history. Sir, personally, I remember, when very eminent newsreaders were there. They were speaking from Delhi. Very promptly their communication was made to the entire nation. But, over a period of time, these regional languages have been neglected by the All India Radio, in particular. And, now, I am hearing, that these have been shifted to the State capitals. I want to know whether the hon. Minister would take the corrective action and these are put in place

in Delhi, and proper care is taken for those regional languages, news-reading in particular. The people in the rural areas, as I have told you, solely rely on the radio, and especially communicated through the respective languages. News broadcast from the national capital always has a special place of importance in regard to credibility, authenticity as well as promptness. It will be a gross injustice to shift the regional languages units from New Delhi or the national capital. The people in the respective States do not want to share the burden while the staff members and the casual newsreaders show a kind of unparallel passion to serve it.

Sir, I must say that there are a number of casual newsreaders in the regional languages. Even though this is a perennial job, there are a number of casual newsreaders there. My colleague, Shrimati Brinda Karat has pointed out about the problems of the employees of the Prasar Bharati or Doordarshan or in the All India Radio. I will particularly say that there are a number of casual news-readers particularly in the All India Radio. Their last pay revision took place in 1997. For over a period of these nine years, there has been no revision. Whatever they are getting today, that is a very paltry sum. Moreover, the working hours have been increased and shifts have been merged. So, the news-readers are being forced to do extra work with less remuneration. So, I would like the hon. Minister to look into this very important issue of news readers, particularly the casual news-readers, because you are not recruiting the regular news readers, you are going by the casual news-readers, particularly in the regional languages. I want to know whether the hon. Minister would kindly ensure that justice is done to these newsreaders.

Sir, my next point is about professionalism of these news-readers. It cannot be, unless proper orientation training is given to them. In these casual news readers, there are many newcomers. They have to read the news, and they have to rely on the Teleprompters. On these Teleprompters one has to get to get the proper training to read the news. But, unfortunately, the mechanism, perhaps, is not in place so that they can really deliver the responsibility bestowed on them. (*Time-bell*) I will just conclude. What I was talking about is, there is a disparity among the English News readers, Hindi News readers and the Regional Languages News readers. So, Sir, I urge upon the hon. Minister to see to it and take the corrective actions. The number of news-bulletins have increased manifold. Additional recording features such as comments from Press, spotlight, NOP, live interaction with the correspondents and so on have

made the responsibility very tough for the news readers. I have talked about technological upgradation and use of Teleprompters and one has to be acquainted with that. The training, the proper training, proper environment, conducive environment has to be made for that. Sir, I am told that the Prasar Bharti has surprisingly withdrawn the transport facility to the casual news readers. Earlier there were transport facilities given to them and in odd hours they used to be carried from their residences and put back to their residences. All of a sudden I hear that there is a change in the Prasar Bharti activities and they have stopped this transporting the casual news readers. I would like to know whether the hon. Minister would assure this House that proper justice will be done to the news readers and the staff of the regional languages. This is a very important matter where the hon. Minister has to intervene. Another point which I would just like to mention is only a tangential mention because I cannot go into details. Sir, in this country of ours TRP is done by some broadcasters only, by the sister organisations of those broadcasters, particularly the multinational broadcasters. The TRP is being done by these broadcasters and this TRP is very much tilted only to promote them. They only put the numbers for particular channel, what is of their origin, they will put 100 and for Doordarshan they will be putting 10. So, TRP is going down for Doordarshan. These channels are making immense profit by doing this TRP manipulation. I would like to know whether the hon. Minister will assure that the TRP will be done by an independent organisation as there is some ORG, Operation Research Group or other organisations like this of Indian origin. They should do the TRP. The Government should take up the responsibility of doing the TRP and decide about the channels and it should propagate it to the people so that the TRP manipulation is not done.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I am not in favour of regimented culture. At the same time, I am also not in favour of losing everything or making everything wide open for the profit of some of the channels. In this world today, Sir, culture is also being termed as a commodity and the commodity is selling. It requires a hard-hitting campaign and at the same time, the very objective of selling is making super profit. Now, the channels that are making super profit must be controlled and the Government must see to it that unnecessarily our value-systems are not trampled with. With these few words, I conclude and thank you very much.

श्री उपसभापति : श्री राम नारायण साहू। आप 3 मिनट में बोलिए, क्योंकि आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है।

श्री राम नारायण साहू (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मेरे पास बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब मैं कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर बोलना चाहता हूँ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : उनमें से आप एक-दो सब्जेक्ट्स पर बोलिए।

श्री राम नारायण साहू : अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप मुझसे कितना बोलवाते हैं। यह सबको मालूम है कि सवेरे भी क्वैश्चन ऑवर में हमारे साथ अन्याय हुआ, तो हमें उसी का कुछ समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति : देखिए, हर पार्टी का समय होता है। यह पूरा डिसकसन 4 घंटे में होना है।

श्री राम नारायण साहू : ठीक है। आप ही की बात रहेगी।

मैं केवल पिक्चर के बारे में बोलूँगा। बहुत सब्जेक्ट्स हैं। आजकल की जो पिक्चरें हैं, मैं उनके बारे में बतलाना चाहूँगा। उपसभापति जी, वैसे तो भारत को एकता की कड़ी में, एक करने में भारतीय फिल्मों का बड़ा योगदान रहा है। खास कर हिन्दी का प्रचार करने में जितना भारतीय फिल्मों का योगदान रहा है, उतना शायद किसी भी चीज़ का नहीं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भले ही करोड़ों-अरबों रुपए खर्च किए हों, लेकिन वह लाभ नहीं मिल पाया है, जो हिन्दी पिक्चरों से भारत को लाभ मिला है और हिन्दी को लाभ मिला है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस समय जो सिनेमा का व्यापार है, मैं समझता हूँ कि सबसे घाटे का व्यापार है। सिनेमा के अन्दर एक जमाना था, मैंने देखा था, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि जब सन् 60 में 'मुगले आज़म' रिलीज हुई थी, तो एक हफ्ते पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी और कब के टिकट बिक गए थे। आज टाइम यह है कि पिक्चर जिस दिन लगती है, बड़ी-से-बड़ी पिक्चर लगती है, उसके पहले दिन का पहला शो ही फुल नहीं होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है - पाइरेसी और दूरदर्शन। मैं आपको दूरदर्शन के बारे में भी बतलाना चाहूँगा। इसके बारे में सब अपने-अपने एंगल से बता रहे हैं, मैं भी अपने एंगल से बताऊँगा।

महोदय, जो पाइरेसी है, वह आपकी सरकार के अन्दर है, क्योंकि जब सरकार पिक्चरों को सर्टिफिकेट वगैरह देती है या मंत्री जी, आपका मंत्रालय देता है, तो जो ये सीडी वगैरह बनती हैं, तो अगर जिस पिक्चर की सीडी के राइट्स प्रोड्यूसर बेच देता है, तो उस पिक्चर को तो सेंसर सर्टिफिकेट ही नहीं मिलना चाहिए। उसको अपने राइट्स 6 महीने बाद बेचना चाहिए। होता क्या है कि जैसे ही पिक्चर रिलीज हुई और अभी जैसा बताया गया कि आप दिल्ली के अन्दर ही चले जाइए, चाँदनी चौक के अन्दर ही चले जाइए, तो जैसे मूँगफली और रेवड़ी वगैरह बिकती है, उस तरह से वह बिक रही है। बेचारे सिनेमा हॉल वाले मजबूर हैं। लाखों-करोड़ों रुपए का सिनेमा हॉल बनवा कर न तो अब उनके पास पैसा है, न उसे तोड़ कर वे दूसरा बिजनेस कर सकते हैं और मजबूरन उसे चलाए जा रहे हैं। अब उसके अन्दर कुछ पूँजीपति लोग आ गए हैं, जो मल्टीप्लेक्स बना रहे हैं। जो मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, उन्होंने इस सिनेमा उद्योग को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। अब देखिए कि हिन्दुस्तान के अन्दर कितने मल्टीप्लेक्स हैं, केवल 150 मल्टीप्लेक्स होंगे, अगर पूरे भारत को देखा जाए, तो 200

मल्टीप्लेक्स होंगे। अगर पूरे भारत मे देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि कम-से-कम 20 हजार सिनेमा हॉल तो होने ही चाहिए। अगर आप एक सिनेमा हॉल के अन्दर औसत रख ले कि उसके अन्दर 15 आदमी वर्क कर रहे हैं। अगर एवरेज देखें तो 15 आदमी काम कर रहे हैं, हर परिवार के पीछे 5 आदमी काम कर रहे हैं। उससे 5 आदमी की रोटी चलती है। तो 5 से डेढ़ सौ आदमी हो गए, अब 20 हजार से कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने आदमियों की रोजी-रोटी पर हमला बोला जा रहा है? इस के ऊपर गवर्नमेंट कोई रोक नहीं लगा रही है। दरअसल यह सेंट्रल गवर्नमेंट है, यह भारत की सब से बड़ी सभा है, यहां यह निर्णय होना चाहिए कि सी0डी0 आए, लेकिन पिक्चर रिलीज होने के 6 महीने बाद प्रोड्यूसर उसको बेचे। सर, प्रोड्यूसर कभी समझ नहीं पाता कि वह अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको तो डिलीवरी के समय पैसा चाहिए। उसने 5 करोड़ में सी.डी. के राइट्स बेच दिए और डिलीवरी के समय पैसा ले गया और वह समझता है कि बहुत हैल्प हो गयी, लेकिन उसको समझ नहीं है। कहते हैं कि देवदास फिल्म 50 करोड़ में बनी थी, अरे भाई 50 करोड़ मे न बनाओ, 45 करोड़ में बनाओ, लेकिन पिक्चर तो कम-से-कम चलनी चाहिए। आज कितनी पिक्चरें हैं जो 4-6 हफ्ते चल पाती हैं? कहां पहले पिक्चरें सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली किया करती थीं। तो यह एक चीज है जिस तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा।

महोदय, आपने टाइम कम दिया है, इसलिए बहुत ब्रीफ में अपनी बात रख रहा हूं। मैं दूरदर्शन के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी कोई पिक्चर रिलीज होती है, तो वह "सी" सेंटर में रिलीज भी नहीं हो पायी है कि वह पिक्चर दूरदर्शन पर आ जाती है। दूरदर्शन को चाहिए कि वह पिक्चर रिलीज होने के 6 महीने बाद नयी पिक्चर दिखाए। कृपया मंत्री जी, इस पॉइंट को नोट कर लें। हम पिक्चर दिखाने से मना नहीं करते, आखिर 40-40 करोड़, 50-50 करोड़, 60-60 करोड़ की पिक्चरें बनती हैं और अगर वे फेल हो जाती हैं तो उन लोगों का क्या होगा जिनके लाखों-करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री मे लगे हुए हैं?

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह आम बजट है, तो हेमा जी ने उसमें पॉइंट आउट किया था कि यह आम बजट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे कला के क्षेत्र से जुड़े लोगो पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं निकाली है। यहां बहुत से लोगों का हवाला दिया गया, चाहे वे फिल्म लाइन के हों, चाहे रंगमंच के रहे हों, even स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के बारे में हम बताना चाहेंगे। उन्होंने अपने जमाने में चाहे जो झंडे गाढ़े हों, लेकिन आखिरी टाइम में उनको कोई देखने वाला नहीं हुआ। तो ऐसे पुराने लोगों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। अभी भारत भूषण का हवाला दिया गया कि इतने बड़े कलाकार का end कैसे हुआ? इस तरह के बहुत से कलाकार हैं, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। आप स्पोर्ट की लाइन में देख लीजिए, आप ध्यानचंद को देख लीजिए। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, लेकिन जब उनका आखिरी समय आया तो उन्हें इलाज के लिए सरकार से पैसा नहीं मिला और उन्हें जो गोल्ड मैडल मिले थे, उनको गलाकर उन्हें अपना इलाज करवाना पड़ा। तो सरकार को दूरअंदेशी होना चाहिए और सरकार की तरफ से जो पिक्चरें बननी चाहिए, उसके लिए हमारे लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, बनाने वाले और दिखाने वाले, ये कहां से लाकर बिठा दिए जाते हैं? यह देखना चाहिए कि उनको कुछ अनुभव है या नहीं है, कुछ जानकारी है या नहीं। अभी जो पिक्चरें बन रही हैं, ये लोगों को क्या संदेश दे रही हैं? हमारे यहां पहले बच्चों की जो पिक्चरें

बनी थीं, उनमें पहली पिक्चर थी "जागृति", "हम पंछी हैं एक डाल के", राजकपूर जी की पिक्चर बनी थी "बूट पॉलिश" और एक पिक्चर बनी जोकि जया जी की पहली पिक्चर थी "गुड्डी।" यह बच्चों के ऊपर बनी एक अच्छी पिक्चर थी, मनोरंजक पिक्चर थी और उसमें एक बढ़िया संदेश था। उस पिक्चर को पूरे भारत में लोगों ने लाइक किया। वह पिक्चर सुपर-हिट हुई, लेकिन आज फिल्मों में क्या परोसा जा रहा है? हमारे यहां 45 साल पहले "मदर इंडिया" पिक्चर बनी थी। उसमें दिया संदेश आज भी सही बैठता है। आज आप देख रहे हैं कि हर प्रदेश के अंदर किसान लोग आत्म-हत्याएं कर रहे हैं। इस प्रदेश में 4 हजार ने की, उस प्रदेश में 5 हजार ने की, लेकिन वह सीन मदर इंडिया फिल्म में 45 साल पहले दिखाया गया था। मंत्री जी, इसके ऊपर ध्यान दें।

श्री उपसभापति : प्लीज, आप समाप्त करें।

श्री राम नारायण साहू : सर, खैर मैं आपके अनुशासन को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन जो बातें मैंने यहां कही हैं, उसके लिए मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि अगर हमने इस पर कम बोला है, तो इसको उतनी ज्यादा तरजीह दी जाए और ज्यादा वजनदारी से ध्यान दिया जाए। आपने मुझे इतना बोलने का टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री कृपाल परमार। आप सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद, उपसभापति जी। मुझे मालूम है कि जब मेरी बारी आती है, तो पांच मिनट ही बचे होते हैं। खैर, मैं पांच मिनट में ही कुछ अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास करूँगा । इस समय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं और इनका मंत्रालय निर्माताओं से डील करता है, अभिनेताओं से डील करता है, टीवी चैनलों से डील करता है, कैबल आपरेटरों से डील करता है, लेकिन अंत में जाकर उपभोक्ता का नंबर आता है, तो उसके प्रति यह मंत्रालय उदासीन हो जाता है।

मान्यवर, अश्लीलता की बात हुई, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। किस तरीके से शराब और तम्बाकू के विज्ञापन आज भी सोडा के नाम पर या दूसरी तरह दिखाए जा रहे हैं, उनका भी मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जैसा यहां पर जया बच्चन जी बोलीं, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी पायरेसी के बारे में बोले, मैं कहना चाहूंगा। मान्यवर, 8 अगस्त, 2005 के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी ने कहा था कि फिल्म पायरेसी में वार्षिक घाटा 1200 करोड़ रुपए का है और जहां तक संगीत उद्योग का संबंध है, भारतीय संगीत उद्योग ने सूचित किया है कि इस उद्योग का घाटा इस चोरी के कारण वर्ष 1999 में 1,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2000 में घटकर के यह 500 करोड़ रुपए का रह गया। यानी पायरेसी के कारण इस उद्योग को भी 500 करोड़ का घाटा हो रहा है। एनडीए सरकार से पहले फिल्म इंडस्ट्री को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता था, इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं मिलता था, मगर एनडीए सरकार के समय में इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं एक इंडस्ट्री को मिलनी चाहिएं, उनसे यह आज भी वंचित है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इतने बड़े उद्योग को अगर सरकार कुछ दे नहीं रही है, तो कम से कम इसको बचाने का प्रयास तो करे।

मान्यवर, मेरा दूसरा विषय, जहां तक टीवी चैनल्स का सवाल है, आजकल गला-काट प्रतिस्पर्धा में विदेशी, देशी और डीडी तीन प्लेयर्स यहां पर हैं। एक प्रश्न के उत्तर में माननीय

मंत्री जी ने कहा था कि देश की 51 फीसदी आबादी को दूरदर्शन की कवरेज उपलब्ध है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जिस ट्राइ का जिक्र कर रहे है, जैसा माननीय रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा और राजीव शुक्ल जी ने भी कहा, अगर यह 51 फीसदी लोगों तक दूरदर्शन की पहुंच है, तो यह पांच क्यो है? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जो इस संबंध में एक निजी कंपनी के हाथ में सिलसिला है, उसके लिए वे एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाएं ताकि यह जो विज्ञापन के बाजार में इतना घोटाला हो रहा है, उससे दूरदर्शन को और दर्शकों को बचाया जा सके।

उपसभापति महोदय, जहां तक मैंने चौथी कड़ी उपभोक्ता की बात की थी, इसके बारे मे सदन मे बहुत कम चर्चा हुई है। आप तो जानते ही हैं कि मैंने एक स्पेशल मेंशन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से दिनांक 16 मार्च, 2000 को पूछा था कि क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है, जहां पर पे-चैनल जो हैं, वे एडवर्टाइजमेंट भी दिखाते हैं और लोगों से रेवेन्यू भी इकट्ठा करते हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक दुनिया में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, जहां पर पे-चैनल लोगों से भी पैसा उगाही करते हैं और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी धन एकत्रित करते हैं। इस तरीके का ड्यूल रेवेन्यू कलेक्शन का उदाहरण दुनिया भर में कहीं नहीं है। दिनांक 28 जून, 2005 को फिर से माननीय जयपाल रेड्डी जी, जो हमारे काबिल मंत्री इस मंत्रालय के पहले थे, उन्होंने कहा था -"I have got the matter examined that the TV pay channels draw revenue from the two sources." अब अगर सरकार को यह जानकारी है और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता, तो यह सरकार अपने उपभोक्ता को करोड़ों-करोड़ रुपए की चपत लगते हुए क्यों देख रही है? हमारी सरकार के दौरान रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की बात हुई थी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप उपभोक्ता के हित के लिए इस तरह उदासीन न रहिए, उपभोक्ता आपका वोटर भी है और उपभोक्ता इस पूरी इंडस्ट्री की जान भी है, उसको बचाने का प्रयास करिए। फिल्म इंडस्ट्री को पाइरेसी से बचाइए, उपभोक्ता को डबल रिवेन्यु की मार से बचाइए। इस तरीके से उदासीन मत रहिए। मैं टी0वी0 चैनल पर आने वाले एक ऐड से अपना वक्तव्य खत्म करूंगा कि *"मेरा बोलना तो एक बहाना था, मेरा मकसद तो सरकार को जगाना था।"* मंत्री जी, चैन से सोना है तो अब जाग जाइए। धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I would like to refer to the attack, I would say, a merciless attack made by certain Members against Doordarshan. These Members and others forget about the entire revolution brought about by Doordarshan in this country. There is no parallel in the history of the world where such a network has been created in the nook and corner of the country. Whether it is in America or USSR or anywhere in the world, such a network has never been established. This is a record in the history of the world and in the media. So, let us no forget this aspect.

Secondly, I would like to accept that even when I was a college student, Smt. Jaya Bachchan was the idol for me. I was her fan right from the age of 13-14 years. I have seen almost 90 per cent, or, perhaps, 95 per cent of her films. But, you must not forget that those who lived in *jhopries*

in this country, who have never gone to any cinema theatre, these people in small, small places have seen on Doordarshan *Guddi*, *Koshish*, *Shor* and other movies. They have seen new movies also. They never go to theatres. Therefore, you should never forget what Doordarshan has done to you as actors and actresses. I can understand, there are weaknesses. I am also going to point out certain weaknesses in Doordarshan. But, nevertheless, we should never forget this historical aspect. What has been referred to... ...(*Interruptions*)...

SHRI SHATRUGHAN SINHA: Sir, we are not making fun of Doordarshan. We do not deny the fact that this is the most potent Institution we have today. As far as taking us all over the country is concerned, Doordarshan has played a number one role, but what we are talking about is how to make it more believable, and develop more credibility in it. This is what we are talking about. Thank you, Sir.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Now, we have talked about the International Film Festival. This is one of the important tasks before your Ministry, Sir. It is only two years old. In 2004, Shri Ravi Shankarji, you had taken the initiative. There is no doubt about it. In 2004, your Government there made a mess of this International Film Festival. They created illegal constructions throughout the Panaji city. And, people were damn against such an International event, so much so, they even said, "You please postpone it." The people of Goa had to say... ...(*Interruptions*)... I am telling you.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I must say that I had gone there. ...(*Interruptions*)... It will not be fair. ...(*Interruptions*)... The Festival had become a craze. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: And, subsequently, whatever works you did illegally there, we faced the consequences in 2005. And, when our Government came in 2005, the Film Festival was conducted very smoothly and without any controversy. Now, Sir, there is a task before you. ...(*Interruptions*)... A task is there before you to conduct all International Film Festivals... ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I would not like to ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, let him finish first. ...(*Interruptions*)...

6.00 P.M.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am talking about my involvement in the Film Festival, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, let him finish first, then, if you want to speak... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has yielded, that is why, she is speaking.

श्रीमती जया बच्चन : मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप जो कह रहे हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया गया, यह गलत बात है, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग में बहुत-सी चीजें हैं, जहां मैं खुद ऐज़ ऐन इंडिविज्युअल इन्वॉल्व थी, जहां गड़बड़ हुई और इस बारे में श्री एस0 जयपाल रेड्डी जी से मेरी बात हुई। I recently did a retrospective of Rshikesh Mukherjee's films. There were a lot of mistakes. I do not know what happened ultimately. So, let us not talk about उस वक्त जो पिछले थे, वे बुरे थे और हम हैं तो अच्छे हैं, आप यह बात मत कहिए, यह गलत बात है।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: You have got reasons to criticize the 2005 Film Festival ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, I am on the subject. You have got different reasons. I know that. But we will not be referring to that. But, Sir, if you want to continue the International Film Festivals in a proper manner, I would request you that as a Minister for Information -- CBI is inquiring into the 2004 Film Festival -- kindly expedite that inquiry. Then, things will come out properly.

Sir, now, I will make one or two points regarding my State. Since you are there, I am taking this opportunity. Sir, you will be surprised to know although we are hosting International Film Festivals, still, Goa does not have a full-fledged Doordarshan Kendra. Forget about that; in a State like Goa which is, internationally famous, we don't have even a two minutes' news bulletin. Can you imagine that? I made some efforts. I started my efforts right from Shrimati Sushma Swarajji's Ministry, then, you also took up that matter. After my efforts, ultimately, during Shri Jaipalji's regime, one Doordarshan studio was granted, progress is on, and plans are now being prepared. Kindly expedite that thing, Sir. Similarly, you will be surprised to know that we come to know about the events taken place in a day in this State by listening to one news bulletin which is telecast at 7.20 p.m.

Throughout the day, we come to know about all the events taking place in New York, or anywhere in Paris, but we come to know about Goa news only through the 7.20 AIR bulletin. That is the only bulletin we have. Therefore, kindly modernise this All-India Radio. Start some News bulletin again.

Secondly, Sir, I would say that as far as our own coverage is concerned -- we should not say much about it, -- the point is that even Doordarshan gives the coverage on 'Today in Parliament' in a very insipid manner. Is the Question Hour covered properly? Are our debates also covered by Doordarshan? Unless Doordarshan takes the initiative, the other channels will not respect us. Hardly one or two questions are touched at the prime time. That is all. That is the only coverage we get. Now, you may say that we have got two separate channels -- Rajya Sabha Doordarshan and Lok Sabha Doordarshan. Nobody is showing those channels, in spite of the compulsions ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is where I want that the Minister should look into it. In fact, the law says that the cable operators, who are not showing Rajya Sabha and Lok Sabha channels, they can be prosecuted. But, I am sorry to say,-- in fact, as a Deputy Chairman I have written to various Governments also -- that they are not implementing the cable rules and they are not showing the Parliament Channels. I hope that this would be looked into.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Then, Sir, as far as the news which is telecast by private channels is concerned, -- of course, we can't dictate terms when we have got our Constitution -- the question is that when one leader of a political party says that his phone is being tapped and he accuses my party leader by name, how can any coverage be given by any private channel to that? How can we tolerate this? Since your telephone is being tapped, you take the name of the leader of a political party, without any responsibility, and any private channel telecasts this! Sir, you have to take a note of all these things. The point is, I can understand distortions here and there, but we can't check every distortion. But, this was a serious thing done recently by one leader of a political party.

Then, Sir, as far as TV channels are concerned, there are many channels. Last time also, we said this and there was a discussion here. People come on television channels and claim medicinal benefits. They say that you will become slim if you take a particular type of medicine; your skin

will become fair if you apply a particular type of soap or lotion. Is the freedom available to distort a fact or to tell an untruth? Is there any law or are we going to check these aspects of advertisements, or, are we going to give all freedom to them that you can say anything about your product and you are allowed to do the same? Therefore, as far as advertisement is concerned, there must be some sort of code of conduct. Out of advertisements, models earn crores of rupees. Of course, we can't prevent them from earning crores of rupees. Sir, stars like Sachin Tendulkar or Shah Rukh Khan or, even Amitabhji, are entitled to charge for such advertisements. But we have to see that when they charge for it and the producers pay -- it is the industrialists which pays to them -- it is actually the tax that a consumer pays directly. This is apart from the Budget. In Budget, Chidambaramji may say 'soaps are not taxed', but, here, through advertisements, people are indirectly charged and taxed heavily. A soap may cost five rupees, but because of the advertisement, it costs ten rupees. So, this aspect of indirect and hidden taxation has to be looked into by the Ministry.

Lastly, Sir, as it was pointed out initially by some hon. Member, I would like to know whether the Government can accept the idea of State funding of elections. The State funding of elections is okay, if it is done. But this is a different method of State funding. It has to be looked into. In 'India Shining' advertisement, crores of rupees of the Government were used by a political party for election funding because some months before the elections, the 'India Shining' programme was there and the State funds were directly given for that purpose, and, therefore, electoral benefits were there. Therefore, there should be a thorough inquiry into what types of funds were given, what was the amount and how it was utilised. Thank you, Sir, for having given me an opportunity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy. You are the last speaker, and you have requested to speak for two minutes only.

SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, I will finish in only two minutes. Sir, I heard with rapt attention some of the hon. Members making a lot of criticism about Doordarshan. I agree that some of them were constructive criticism. But, Sir, the role of Doordarshan whether it is in the field of education, disseminating information to the people, especially, the student community, or whether it is in the fields of science and technology, health sector, culture, etc., cannot be overlooked. I can say with authority that no other private channel, none of them, has covered these aspects because

the Doordarshan is not run for profit alone. It is for the society. In educating the society on various aspects and helping the society, Doordarshan has been doing a wonderful job. Sir, some criticisms have come from here and there. Some political parties have been given projections; some political leaders have been given projections. Sir, I have not seen any programme that gives political mileage to any political party. I have not found it in any of the programmes that are being telecast by Doordarshan. However, on the other hand, some of the private channels are being used in some States and also at the national level by some political parties to promote their party's interests. It is happening there.

Sir, as far as the AIR is concerned, with a coverage of more than 99 per cent of the area, I would like to say that it is giving the best news to the people. So, as far as the AIR is concerned, it deserves appreciation. Sir, last time also when I participated in the debate on regulating the private channels, I requested the hon. Minister that there should be a legislation to regulate the private channels because the criticism that has come on the private channels which are telecasting films, programmes, and so many other things, is about the violation of the rules. I want the hon. Minister to regulate them. There had been a similar demand when hon. Member, Shri Ravi Shankar Prasad, was the Minister for Information and Broadcasting. The same question had been put by various hon. Members, irrespective of the political parties they belonged. Sir, I think, there should be a regulation on the programmes telecast by the private TV channels. It is very important because in this country, a kind of vilification campaign, maligning the political leaders, is going on, in a big way, for purposes of making money by these private television channels. It needs to be stopped. Therefore, Sir, I want the hon. Minister to reconsider this.

Coming to my State, we have got the Doordharshan Kendra, which is quite old. Shri Ajit Panja was the then Minister; he is also from West Bengal. He came and inaugurated the studio, the production unit, there. More than 75 people are working there for a ten minutes' News programme. For only ten minutes' News programme, more than 75 people are working! Most of them are coming from Chennai. They come on Mondays, return on Fridays and there is nobody on Saturdays and Sundays. All the officers and people working in the production unit go away. The Doordarshan Kendra is practically dead because we are using only the National channel, which has been telecasting the programmes.

Sir, Pondicherry is a place of international repute because of the presence of Indian and French cultures. There is the Aurobindo Ashram and the international city Auroville; it has got its importance. But, the local News is not covered and the production unit of Doordarshan Kendra in Pondicherry is not at all working. Then why do you have it? Please, close it. Why do you have that unit? Assurance was given on the floor of the House, when the issue was raised by me through a Special Mention, that they would look into the matter. So far, nothing has been done.

Therefore, Sir, I want the hon. Minister to consider the matter and see to it that as far as the issue of production is concerned, it should be useful to the people of the State. Beyond 20 K.M., we cannot watch the programme; only 20 K.M. radius is covered. Therefore, Sir, I want the hon. Minister to increase the coverage area and see to it that the production unit functions efficiently. Otherwise, for heaven's sake, close it!

SHRI JANARDHANA POOJARY : Sir, I would take just a minute. It is heartening to note, for the first time, that the entire battery of officers is in the gallery. That shows how much importance the hon. Minister is giving to the views expressed by the hon. Members. This is an exemplary act that also shows that he has got control over the department...*(interruption)*... It shows what importance he is giving to the Members of Parliament's views. This needs to be followed by other Ministries as well. I have been observing this, and even while the discussion on the Finance Ministry was taking place, very few officers were present here. Here we see that all the officers are listening to the views of the hon. Members with rapt attention. I compliment the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. The discussion on the Working of the Ministry of Information and Broadcasting is concluded. The reply will be taken up later. The date would be informed.

The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

The House then adjourned at thirteen minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 14th of March, 2006

MGIPMRND—149RS—06-9-2006